R.N.I.Regd.No.:RAJHIN/2005/16223
Postal Regd.No.:JAIPURCITY/108/2019-21

कृषि, सहकारिता, पशुपालन व ग्रामीण विकास का अग्रणी साप्ताहिक समाचार पत्र

हलधर टाइम्स

www.haldhartimes.in

@ 8

IF UNDELIVERED PLEASE RETURN TO
हलधर टाइम्स
सी-17, पुरोहित जी का बास,
सरकारी मिडिल स्कूल के पास,
22 गोदाम, जयपुर-302006

163.73 लाख हैक्टयर में खरीफ | @ 3 | मूल्य : ₹ 5/- पृष्ठ : 8 | जयपुर | वर्ष-14, अंक-30 | 20 मई - 26 मई, 2019 | (वार्षिक मूल्य : ₹250/-)

हलचल

15 जुलाई तक भू-राजस्व वसूली पर रोक

जयपुर (कास)। प्रदेश के अकालग्रस्त जिलों में भू-राजस्व वसूली अब 15 जुलाई तक नहीं होगी। राज्य सरकार ने वसूली 15 जुलाई तक नहीं करने के आदेश जारी किए। आदेश के अनुसार ऐसी भूमि जो भू-राजस्व वसूली में प्रभावी नहीं होंगे, जो भू-अभिलेख में तो बारानी, तालाबी अथवा सैलाबी अंकित है। किन्तु , उन भूमियों पर कुआं अथवा दूसरे स्त्रोतों से सिंचाई होती है। चूरू बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, हनुमानगढ़, पाली, जालौर और नागौर जिलों के 5 हजार 555 गांव घोषित किए गए थे। पहले यहां भू-राजस्व की वसूली 28 फरवरी 19 तक स्थगित की गई थी।

28 को आएगा जेट का परिणाम

जयपुर (कास)। कृषि विश्वविद्यालय, कोटा के द्वारा कृषि स्नातक, स्नातकोत्तर और विद्यावाचस्पति में प्रवेश के लिए 12 मई को आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा(जेट) का परिणाम आपत्तियों के निस्तारण के बाद 28 जुलाई को घोषित किया जायेगा। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय ने परीक्षा आयोजन के बाद 19 मई तक 500 रूपए शुल्क के साथ छात्रों से उत्तरकुंजी पर आपत्ति मांगी है। विश्वविद्यालय का कहना है कि जिन छात्रों की आपत्ति सही पाई जाती है, उनको शुल्क वापिस कर दिया जायेगा।

उर्वरक प्रशिक्षण आज से

उदयपुर (कास)। महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रसार शिक्षा निदेशालय के द्वारा खुदरा उर्वरक विक्रय प्रार्थकार पत्र हेतु 15 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आज से आयोजित किया जायेगा।

सैद्धान्तिक परीक्षाएं 23 से

जोधपुर (कास)। कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर के अन्तर्गत आने वाले कृषि महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की सैद्धान्तिक परीक्षाएं 23 मई से शुरू होगी। विश्वविद्यालय के जनसम्पर्क अधिकारी एमएल महेरिया ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय के द्वारा प्रायोगिक परीक्षाएं सम्पन्न करवाई जा चुकी है।

पाठक बने पत्रकार

हलधर टाइम्स के पाठक खेती / पशुपालन से जुड़ी समस्या, फोटो, जानकारी व्हाट्सएप के इन नम्बरों पर भेजें।

9828165521
8058835320

www.haldhartimes.in

आइएचआईटीसी द्वारा आयोजित किए जाने वाले किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम

बजट में अंधी, खेल रहे है बंधी-बंधी

प्रशिक्षक के जाली हस्ताक्षर से उठाया बजट

जयपुर (कास)। जितनी बंधी, उतना बजट। किसान प्रशिक्षण की बजट फाइल पर स्वीकृति में ना-नुकर की रत्तीभर भी गुजाइंश नहीं। ऐसा ही कुछ हो रहा है इंटरनेशन हार्टिकल्चर ट्रेनिंग एडं इनोवेशन सेंटर दुर्गापुरा में। इस सेंटर में प्रत्येक काम के लिए जिम्मेदारों की बंधी बधी हुई है। वहीं, उद्यानिकी निदेशालय आंख बंद करके बजट खपाने में जुटा है। बजट का उपयोग कहां, किस तरह करना है, इसका खाका प्रशिक्षकों से बंधी लेने वाले संस्थान के दूसरे कार्मिक स्वयं तैयार कर देते है। कागजी खाना पूर्ति से लेकर जयपुर से 400-500 किलोमीटर दूर बैठे प्रशिक्षक के हस्ताक्षर भी फाइल पर कर दिए जाते है। फर्जी हस्ताक्षर करके लाखों रूपए का बजट उठा लिया जाता है। उद्यान विभाग से सेंटर के द्वारा जून 2018 में किसान प्रशिक्षण के नाम पर कुछ इसी तरह एक लाख रूपए का बजट स्वीकृत करवाया गया है। सूत्रों के अनुसार बाड़मेर जिले में अनार उत्पादक किसानों के लिए 29-30 जून और 3-4 जुलाई 2018 को प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तावित था। उद्यानिकी निदेशालय ने प्रशिक्षण का जिम्मा मुख्य प्रशिक्षक मुकेश सैनी और सहायक प्रशिक्षक महेश शर्मा को सौंपा था। गौरतलब है कि इससे पूर्व बाड़मेर के बुड़ीवाड़ा गांव में आयोजित किसान प्रशिक्षण का जिम्मा भी इन्हीं प्रशिक्षकों के पास था। जानकारी के अनुसार प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए उद्यानिकी निदेशालय से बजट मंजूर करवाने में, कथित तौर पर सेंटर के कैशियर चन्द्रमोहन अजमेरा और स्वागत के साथ-साथ बिना आदेश के प्रशासन का जिम्मा संभालने वाली सविता ने अहम भूमिका निभाई। आरोप है कि बजट स्वीकृति के नाम पर दोनों ने प्रशिक्षकों से बंधी भी वसूल की है।

यह है मामला

अनार उत्पादक किसानों के लिए 29-30 जून और 3-4 जुलाई 2018 को प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए 1 लाख रूपए का बजट उद्यानिकी विभाग ने आइएचआईटीसी को मंजूर किया था। बजट संबंधी पत्रावली पर जाली हस्ताक्षर किए गए। उद्यान विभाग के अधिकारियों ने भी आंख बंद करके बजट मंजूर कर दिया। सूत्र बताते है कि कथित तौर पर बजट पत्रावली पर मुकेश सैनी के जाली हस्ताक्षर सेंटर के कैशियर के द्वारा किए गए। सेंटर की बजट संबंधी पत्रावली में मुकेश सैनी के अलग-अलग हस्ताक्षर बजट की बदरबांट को स्पष्ट तौर पर दर्शा रहे है। सूत्र बताते है कि बजट स्वीकृत होने के बाद बाड़मेर जिले में प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित ही नहीं हुआ। जबकि, उद्यान विभाग से मिले चैक का भुगतान उठा लिया गया।

अब निगल रहे जिंदा मक्खी

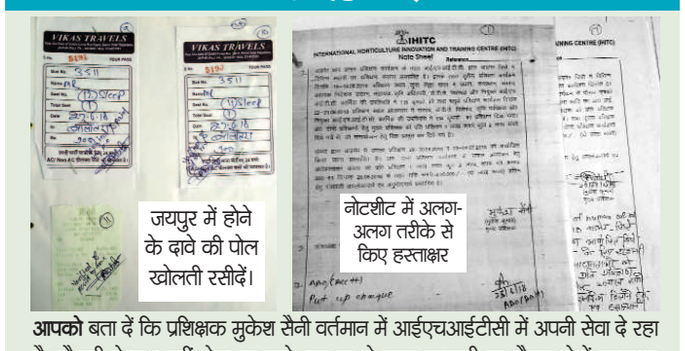

जयपुर में होने के दावे की पोल खोलती रसीदें।

नोटशीट में अलग-अलग तरीके से किए हस्ताक्षर

आपको बता दें कि प्रशिक्षक मुकेश सैनी वर्तमान में आईएचआईटीसी में अपनी सेवा दे रहा है। नौकरी से हाथ नहीं धोना पड़ जाये, इस डर से बजट पत्रावली पर मौजूद दोनों हस्ताक्षर अपने ही बता रहा है। वहीं, कैशियर चन्द्रमोहन अजमेरा भी जिंदा मक्खी निगलने को तैयार बैठा हुआ है। सेंटर में सहायक प्रशिक्षक रहे महेश शर्मा का कहना है कि 5वें चरण के प्रशिक्षण के लिए एक लाख रूपए का बजट स्वीकृत हुआ था। बजट संबंधी पत्रावली पर मुकेश सैनी के जाली हस्ताक्षर किए गए है। जाली हस्ताक्षरों पर बिना गौर किए ही उद्यानिकी विभाग के द्वारा सेंटर को एक लाख रूपए का बजट मंजूर किया गया। उनका कहना है कि पांचवे चरण के प्रशिक्षण के लिए बजट मंजूर उस समय किया गया, जब मुख्य प्रशिक्षक मुकेश सैनी बाड़मेर से चौथे चरण का प्रशिक्षाण सम्पन्न करवाकर जयपुर लौटा भी नहीं था।

ऐसे हुई पैसो की बदरबांट

महेश का कहना है कि जाली हस्ताक्षर से उठाए बजट का उपयोग पाचवें चरण में प्रशिक्षण के लिए होना था। लेकिन, बाद में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ। ऐसे में बजट का उपयोग नहीं हो पाया। जबकि, एक लाख रुपए के चैक को प्रशिक्षक मुकेश सैनी ने भुना लिया। इसके बाद मंजूर हुए बजट का कहां, किस काम में उपयोग लिया गया, कोई रिकॉर्ड सेंटर के पास मौजूद नहीं है।

यह है स्थिति

इस संबंध में प्रशिक्षक मुकेश सैनी से बात की गई तो उन्होंने बजट संबंधी पत्रावली पर स्वयं के जाली हस्ताक्षर होने से स्पष्ट इंकार कर दिया। वहीं, कैशियर चन्द्रमोहन अजमेरा का कहना था कि बजट पत्रावली पर मैं क्यों दूसरे के हस्ताक्षर करने लगा। आपको बता दें कि प्रशिक्षक मुकेश सैनी अलग-अलग पत्रावली पर हिन्दी और अंग्रेजी में हस्ताक्षर मौजूद है। उनके कहे अनुसार वह जयपुर में मौजूद थे। लेकिन, चौथे चरण का प्रशिक्षण सम्पन्न करवाकर मुकेश 27 जून को जयपुर के लिए रवाना हुए है। जबकि, बजट पत्रावली पर 25 जून 2018 की तिथि अंकित है।

डायरेक्टर सविता के इशारे पर

हलधर टाइम्स द्वारा गंताक में 'फर्जी बिलों से धोरी हो रहे है धनी ' शीर्षक से प्रकाशित समाचार के बाद शिकायतकर्ता महेश शर्मा को फोन पर जान-माल का नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई है। धमकी देने वाले का कहना यह था कि उद्यानिकी विभाग के डायरेक्टर सविता के इशारे पर चलते है। आपसी वार्ता में आपत्तिजनक शब्दों का भी जमकर उपयोग धमकी देने वाले ने किया है। वार्ता का यह ऑडियो हलधर टाइम्स के पास सुरक्षित है।

बजट पत्रावली पर हिन्दी में भी मैने ही हस्ताक्षर किए है। मैं अंग्रेजी में भी हस्ताक्षर करता हूँ। उस दिन मैं जयपुर में ही था। किसी ने मेरे जाली हस्ताक्षर नहीं किए है।

मुकेश सैनी, प्रशिक्षक, आईएचआईटीसी, जयपुर

मेरे नोटशीट पर साइन नहीं होते है। मुकेश सैनी के साइन मैंने नहीं किए है।

चन्द्रमोहन अजमेरा, कैशियर, आईएचआईटीसी, जयपुर

सीआईआरजी लैब को एनएबीएल मान्यता

मिला आईएसओ / आईईसी 17025:2005

नई दिल्ली। मथुरा के केन्द्रीय बकरी शोध संस्थान का नाम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) की उन प्रयोगशालाओं की सूची में शामिल हो गया है, जिन्हें एनएबीएल की मान्यता है। सीआईआरजी के निदेशक मनमोहन सिंह चौहान ने कहा कि संस्थान की प्रयोगशाला को जीवविज्ञान परीक्षण के क्षेत्र में आईएसओ / आईईसी 17025:2005 मानक के अनुसार को परीक्षण और मापांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) का प्रतिष्ठित प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थों में रोगाणुओं और उनके विषाक्त पदार्थों की उपस्थिति एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता का विषय है। उनका शीघ्र पता लगाने से खाद्य उत्पाद की गुणवत्ता आश्वासन और खाद्य जनित बीमारियों के प्रकोप को फैलने से रोकने में मदद मिलेगी।

28 से आयोजित होगी कृषि परीक्षाएं

जयपुर (कास)। राजस्थान लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं का दौर शुरू होने वाला है। विभागवार भर्ती परीक्षाएं 27 से 31 मई तक होगी। इनका आयोजन अजमेर जिला मुख्यालय पर होगा। कृषि विभाग में सहायक सांख्यिकी अधिकारी भर्ती परीक्षा 28 मई को सुबह 9 से 11 बजे तक होगी। सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी (एग्रीकल्चर केमिस्ट्री), सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी (बॉटनी) परीक्षा का आयोजन 29 मई को होगा। इसके तहत सुबह 9 से 11 बजे बजे एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और दोपहर 3 से 5 बजे तक बॉटनी की परीक्षा होगी। इसी तरह सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी (प्लांट पैथेलॉजी) परीक्षा 30 मई को सुबह 9 से 11 बजे तक होगी। सहायक कृषि अधिकारी (कृषि विभाग) भर्ती परीक्षा-2018 (टीएसपी-नॉन टीएसपी) का आयोजन 31 मई को होगा। इसमें सुबह 9 से 11 बजे तक सामान्य हिंदी और सामान्य ज्ञान और दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक कृषि विषय की परीक्षा होगी।

नई योजनाओं का तैयार हो रहा है मसौदा

कृषि मंत्रालय की कवायद

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के सातों चरण का मतदान सम्पन्न होने के बाद अब सबको 23 मई को आने वाले परिणामों का इंतजार है। 23 मई का इंतजार मतदाता ही नहीं, कृषि मंत्रालय के अधिकारी भी कर रहे है। मौजूदा सरकार यदि दोबारा सत्ता में बनी रहती है तो किसानों को बड़ी सौगात मिल सकती है। चुनाव परिणाम आने से पूर्व ही कृषि मंत्रालय ने किसानों के लिए रोडमैप तैयार करना शुरू कर दिया है। कृषि, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अधिकारी नई सरकार के लिए पहले एक सौ दिन और पांच साल का विस्तृत एजेंडा तैयार करने में जुट हैं। खेती से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर मंत्रालय जहां अपनी प्राथमिकताओं का मसौदा तैयार कर रहे हैं, वहीं पिछले पांच सालों के दौरान शुरू की गई योजनाओं को रफ्तार देने के तरीके भी तलाश रहा है। खाद्यान्न, दालें, खाद्य तेल, बागवानी उत्पाद, मत्स्य और डेयरी उत्पादों की मांग को पूरा करने के साथ आपूर्ति बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है। मसौदे में कृषि क्षेत्र में सुधार के उपायों के साथ किसानों की आमदनी को बढ़ाने पर जोर देने पर जोर है।

बजट का अभाव

इधर, 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो जाने के बाद भी कृषि विभाग किसानों के लिए योजनाओं का खाका नहीं खींच पा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि नई सरकार गठन के बाद केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में फेरबदल देखने को मिलता है। वहीं, राज्य बजट का बजट भी आचार संहित हटने के बाद ही प्रस्तुत होगा। केन्द्र और राज्य सरकार किसानों के लिए क्या सोच रखती है, इसके लिए थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। आपको बता दें कि कृषि, उद्यानिकी, कृषि विपणन सहित दूसरे सम्बद्ध विभागों ने आचार संहिता के चलते कृषि और पशुपालन से जुड़ी योजनाओं की गाइडलाइन अभी जारी नहीं की है।

खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय को जिम्मेदारी

कृषि उत्पादन बढ़ाने के साथ खाद्य प्रसंस्करण और उत्पादों की मार्केटिंग के उपायों के लिए खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय को योजना तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। नीति आयोग ने भी इसी दिशा में पहल की है। आपको बता दें कि इससे पूर्व भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सचिव स्तर के अधिकारी अपनी योजना कृषि मंत्रालय को सौंप चुके है। मंत्रालय के अनुसार अभी केवल रोडमैप तैयार हो रहा है। नई सरकार ही नए प्रस्तावों पर सहमति अथवा असहमति की मुहर लगाएगी।

इन क्षेत्रों पर फोकस

सूत्रों के अनुसार मंडी कानून और कांट्रैक्ट खेती समेत लगभग एक दर्जन ऐसे अधिनियम है, जिससे कृषि क्षेत्र प्रभावित होता है। मंडी कानून, विपणन व्यवस्था के साथ-साथ मत्स्य पालन, डेयरी, बागवानी और दूसरे क्षेत्रों पर फोकस किया जायेगा।

Mewar University
Knowledge to Wisdom

MEWAR UNIVERSITY
(Mewar University, Chittorgarh Act, 2009 Rajasthan & UGC Approved)

Pesticides and Fertilizer Dealers
ADMISSION OPEN
कीटनाशक एवं खाद व्यवसाय के संचालन के लिए आवश्यक
कृषि एवं कृषि संबंधित विषयों में एक वर्षीय डिप्लोमा

Diploma in Agriculture Extension Services for Input Dealer (DAESI)
भारत की प्रसिद्ध एवं UGC द्वारा मान्यता प्राप्त
मेवाड विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रम

कृषि एवं कृषि सम्बन्धी विषयों में एकवर्षीय डिप्लोमा की उपयोगिता

- पेस्टिसाइड्स (कीटनाशक) लाइसेन्स के नवीनीकरण एवं नये लाइसेन्स बनवाने में अनिवार्य।
- खाद के नये लाइसेन्स बनवाने के लिए अनिवार्य।
- पेस्ट कन्ट्रोल लाइसेन्स के नवीनीकरण एवं नये लाइसेन्स बनवाने में अनिवार्य।
- खाद एवं कीटनाशक की उत्पादक कम्पनीयों से एजेंसी लेने एवं कम्पनियों में नौकरी प्राप्त करने में उपयोगी।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें :
NH -79 Gangrar, Chittorgarh, Rajasthan - 312901
Ph : 9057396566,9785700699
E-mail : daesi@yahoo.com Web.: mewaruniversity.org

विकास | कृषि-खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, मोहाली

अब खेतों में पैदा होगा रंग-बिरंगा गेहूं

वैज्ञानिकों को रंगीन गेहूं किस्म विकास में मिली सफलता

नई दिल्ली। अब जल्द ही गेहूं उत्पादक किसानों के खेतों में रंग-बिरंगे गेहूं का उत्पादन होता नजर आएगा। यह गेहूं नीले, बैंगनी सहित दूसरे रंग में उपलब्ध होंगे। सोच रहे होंगे, कैसे, तो बता दें कि कृषि वैज्ञानिकों ने जैव प्रौद्योगिकी के जरिए गेहूं की ऐसी किस्मों का विकास किया है, जो मल्टीकलर होने के साथ-साथ उच्च पोषकता भी प्रदान करती है। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से प्रदेश के साथ-साथ देश के किसानों का रूझान काले गेहूं की खेती की ओर बढ़ा है। हालांकि, काले गेहूं की खेती करने वाले किसानों की संख्या वर्तमान में काफी कम है। लेकिन, इन किस्मों के बाजार में आ जाने के बाद गेहूं के दाने के साथ-साथ रोटी और ब्रेड का रंग भी बदला हुआ नजर आएगा। गेहूं की रंगीन किस्मों को राष्ट्रीय कृषि-खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, मोहाली के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित किया गया है। साथ ही, विकसित तकनीक का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए संस्थान कंपनियों से करार हस्ताक्षर कर रहा है। ताकि, अनुसंधान लैब तक सीमित नहीं रहे। जानकारी के अनुसार गेहूं की रंगीन किस्मों के विकास में वैज्ञानिकों को दशक का समय लगा है। आपको बता दें कि साधारण गेहूँ की किस्म सुनहरी रंग की होती है।

ऐसे हुआ विकास

गेहूं की रंगीन किस्म तैयार करने में कृषि वैज्ञानिकों ने क्लासिक जैव प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग किया है। जो आमतौर पर पौध प्रजनकों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। कई साल के प्रयासों के बाद वैज्ञानिकों को रंगीन गेहूं की लाइन पेश करने में सफलता मिली है। फिर, इन किस्मों को जलवायु के अनुकूल बनाया गया है।

रंगीन गेहूं के स्वास्थ्य लाभ

रंगीन गेहूं किस्में उच्च पोषक गुणों के चलते कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करेगी। उदाहरण के लिए काला गेहूं वसा जमाव को रोकने में मदद करता है, इंसुलिन सहिष्णुता में सुधार करता है, ग्लूकोज के स्तर और निम्न रक्त कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है। एनएबीआई के शोध में यह खुलासा हुआ है। शोध रिपोर्ट में कहा गया है कि एंथोसायनिन के अलावा रंगीन गेहूं किस्मों में जिंक, प्रोटीन और सूक्ष्म पोषक तत्व होते है। इनमें मौजूद एंटीऑक्सिडेंट उम्र बढ़ने, मोटापे और मधुमेह से बचाने में मदद कर सकते हैं।

28 गुना अधिक एंथोसायनिन

संस्थान की वैज्ञानिक मोनिका गर्ग के मुताबिक गेहूं की सामान्य किस्मों में एंथोसायनिन की मात्रा बहुत कम होती है। लेकिन, रंगीन गेहूं में इस तत्व की मात्रा काफी ज्यादा होती है। इन गेहूं किस्मों में 28 गुना अधिक एंथोसायनिन मौजूद होता है।

10 कंपनियों से एमओयू

रंगीन गेहूं किस्मों के बीजोत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एनएबीआई ने निजी क्षेत्र की 10 कम्पनियों से एमओयू किया है। एमओयू के तहत विकसित प्रौद्योगिकी कम्पनियों का हस्तांतरित की गई है। एमओयू करने वाली कम्पनियों में बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र सहित दूसरे राज्यों की कम्पनियां शामिल है।

बंजर होती भूमि

अपनी बात

आंख बंद करके डाली जा रही रासायनिक खाद भूमि के लिए नुकसानदायक साबित हो रही है। अधिक उत्पादन की चाह में यह बात कोई समझने को तैयार नहीं है। यही नहीं, रासायनिक दवा और खाद के कारण भूमिगत जल और पर्यावरण भी दूषित हो रहा है। किसानों की ओर से रासायनिक खाद, दवाइयां और कीटनाशक का लगातार इस्तेमाल करने से जमीन बंजर बनती जा रही हैं। जमीनों में पोषक तत्वों की कमी घर कर चुकी है। इसलिए, फसलों की वानस्पतिक ग्रोथ तो अच्छी हो रही है। लेकिन, उत्पादन में किसान को नुकसान उठाना पड़ रहा है। जमीन के इस तरह के दोहन की तरफ अब सरकारों को सोचने और ठोस कार्यनीति बनाने की जरूरत है। महंगी रासायनिक खाद उपयोग से फसलों की पैदावार किसानों की अपेक्षाओं के विपरीत हो रही है। नतीजतन किसान खेतीबाड़ी से विमुख होता जा रहा है।

नाइट्रोजन के उपयोग से भूमि में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध पोटेशियम गायब हो रहा है। जमीन में पोटेशियम का अभाव, विटामिन-सी और प्रोटीन की कमी आने से लोगों में कई बीमारियाँ उत्पन्न हो रही हैं। सुपर फॉस्फेट के कारण जमीन में तांबा और जस्ता खत्म होना शुरू हो जाता है। नाइट्रोजन और सुपर फास्फेट के इस्तेमाल से गेहूं और मक्का की फसलों में प्रोटीन की कमी आ जाती है। रासायनिक खाद और कीटनाशक की आसमान छूती कीमतें किसानों की कमर तोड़ती आ रही हैं। रही-सही कसर ट्रैक्टर की महंगी जुताई ने पूरी कर दी है। किसान आपसी देखा-देखी में रासायनिक खादों का उपयोग आंखें बंद करके कर रहा हैं। अगर फसलों की पैदावार की तरफ नजर दौड़ाई जाए, तो उतनी भी नहीं निकल पा रही, जितना फसल की बिजाई का खर्च हो जाता है। प्रकृति में अचानक बदलाव आने से बारिश भी अब बेमौसमी होती है। रासायनिक खादों के सहारे उगाई जाने वाली फसलों को समय पर पानी से सिंचित करना पड़ता है, अन्यथा वह सूख जाती हैं। हजारों रुपए खर्च करने के बावजूद किसानों को न तो पर्याप्त अनाज मिल पा रहा है और न ही पशुओं को चारा। रासायनिक खाद बनाने के लिए फैक्ट्रियों में कोयला जलाना पड़ता है, जिसके चलते पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ रहा है। ऐसे हालात में पशुओं को खिलाए जाने वाली हरी घास भी किस हद विषैली हो सकती है, सोचने वाली बात है। पहले किसान पशुओं का पालन-पोषण किया करते थे। घरों में दुधारू पशु रखना हर किसान की मानो जरूरत हुआ करती थी। पशुओं के गोबर को जमीन में खोदे गए गड्ढे में डालकर उसकी कंपोस्ट खाद तैयार की जाती थी। अक्सर किसान पशुओं का गोबर वैसे भी खेतों में यह सोचकर डालते थे कि उनकी जमीनों में उपजाऊ शक्ति कहीं अधिक बढ़ जाएगी। छह महीने बाद कंपोस्ट खाद को लोग अपने खेतों में डालते थे, उस समय फसलों की पैदावार बहुत अधिक होती और पशुओं का चारा भी किसानों को कभी खरीदना नहीं पड़ता था। बदलते सामाजिक परिवेश के चलते लोगों ने रहन-सहन, खान-पान के तौर-तरीके ही नहीं बदले, बल्कि आधुनिक खेती पर निर्भर होकर जहरीली फसलों की पैदावार करते जा रहे हैं। कंपोस्ट खाद से उत्पन्न की जाने वाली फसलों, फल-सब्जियों का अपना ही एक अलग स्वाद हुआ करता था। रासायनिक खादों के प्रति किसानों के बढ़ते लगाव के चलते हम अपनी सदियों पुरानी खेतीबाड़ी की प्रणाली को भूलते जा रहे हैं। किसान अब पशु पालने का मतलब स्वयं को अति पिछड़ा हुआ मानने लगे हैं। घरों की औरतें पशुओं का गोबर उठाना अब पसंद नहीं करती हैं। कहने को तो सभी मॉडर्न किसान कहलाते हैं, मगर पशु पालना ज्यादातर किसान छोड़ते जा रहे हैं। यही वजह है कि किसान अपने खेतों की जुताई भी ट्रैक्टरों से करवाते हैं। जमीनों के मालिक होने के बावजूद लोग अपने घरों में दुधारू पशु रखने की बजाय बाजार से महंगा दूध खरीदना अपनी आदत बना चुके हैं। अपनी पारंपरिक खेतीबाड़ी से मुंह मोड़ लेने वाले किसान क्या कभी कर्ज के बोझ से उबर सकते हैं, शायद नहीं। सरकारें चुनावी माहौल में किसानों को कर्ज मुक्त करने की कई घोषणाएं करती हैं, मगर वास्तव में किसानों के हालात बद से बदतर बनते जा रहे है। कृषि विभाग किसानों में जागरूकता बढ़ाने संबंधी किसान मेलों का आयोजन करवाता रहा है। किसानों को सस्ते दाम पर फसलों के बीज तक मुहैया करवाता रहा है। यही नहीं, मुफ्त बीज भी किसानों को बांटे जाते रहे हैं। लेकिन, किसान आत्मनिर्भरता का लक्ष्य अब भी कोसो दूर नजर आ रहा है।

संधारणीय खेती समय की मांग

सप्ताह का साक्षात्कार

देश खाद्यान्न उत्पादन में रिकॉर्ड बना रहा है। परन्तु इसी दौर में असंतुलित रूप से कृषि रसायनों का उपयोग कर रहा है। जिससे भोजन, हवा, पानी, स्वास्थ्य और भूमि प्रदूषित हो रही है। इसका प्रभाव हमारे दैनिक जीवन पर भी पड़ रहा है मनुष्यों और जीवों में विभिन्न प्रकार के रोग पनप रहे हैं। वहीं, कृषि रसायनों के प्रति कीट-रोग की प्रतिरोधकता भी बढ़ रही है। इससे कृषि लागत बढ़ रही है। वहीं, किसान की आय घट रही है। इन सब कारणों के चलते किसानों को रसायनों से बचाव के लिए और खेती में टिकाउपन लाने के लिए गंभीरता से सोचना पड़ेगा। आज किसान सस्ती, सरल और टिकाउ खेती की आवश्यकता महसूस कर रहे है। टिकाऊ खेती को लेकर हलधर टाइम्स की डॉ. दिनेश कुमार से हुई वार्ता के मुख्यांश...

जीवन परिचय

रायपुर मेवान (अलवर) से ताल्लुक रखने वाले डॉ. दिनेश कुमार ने नवसारी कृषि विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर और आणन्द कृषि विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। चार बार नेट परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं। इन्होंने अपने कॅरियर की शुरूआत राय विश्वविद्यालय, अहमदाबाद (गुजरात) में सहायक प्राध्यापक के रुप में की। वर्तमान में डॉ. दिनेश कुमार भारतीय मृदा और जल संरक्षण संस्थान, दतिया, मध्यप्रदेश में वैज्ञानिक पद पर कार्यरत है। अब तक इनके राष्ट्रीय और अर्न्तराष्ट्रीय जर्नल में 14 रिसर्च पेपर प्रकाशित हो चुके हैं। इसके अलावा 10 आलेख और 7 सारांश प्रकाशित हुए है।

संधारणीय / टिकाऊ खेती क्या है?

टिकाऊ खेती मिट्टी, वन्यजीवों, फसलों, पशुधन, जंगलों, पादप आनुवांशिकी संसाधनों और पारिस्थितिकी तंत्र सहित नवीकरणीय संसाधनों की एक संतुलित कृषि प्रबंधन प्रणाली है । जो परंपरागत और नवीन कृषि तकनीक समन्वय के साथ, संसाधनों की गुणवत्ता में गिरावट के बिना, वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए आजीविका, उत्पादकता और संसाधनों की पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को बनाएं रखने अथवा सुधारने की जरूरतों को पूरा करती है। स्थायी कृषि को पारिस्थितिकीय अथवा जैविक खेती अथवा प्राकृतिक खेती अथवा पर्माकल्चर के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन, कुछ लोगो के बीच यह गलत धारणा है कि बिना रासायनिक आदानों के, की जाने वाली खेती ही संधारणीय/टिकाऊ खेती है, जबकि यह एकीकृत, कम निवेश आधारित अधिक उत्पादन देने वाली कृषि प्रणाली है।

संधारणीय/टिकाऊ खेती की जरूरत क्यों पड़ी है?

फसल उत्पादन की अत्याधुनिक तकनीकों ने फसलों का उत्पादन तो काफी बढ़ा दिया है। लेकिन, भूमि क्षरण, भूमि उर्वरता में गिरावट, फसल उत्पादकता में कमी, मृदा में लाभदायक सुक्ष्म जीवाणुओं और केंचुओं की संख्या में कमी, फ सल उत्पादों में हानिकारक रसायनों के अवशेष, जीन क्षरण, पशु और मानव स्वास्थय पर बुरा प्रभाव, जल, मृदा, वायु और पर्यावरण प्रदूषण जैसी जटिल - गंभीर समस्याएं पैदा कर दी हैं। आधारभूत प्राकृतिक संसाधनों की गुणवत्ता का स्तर निरंतर गिरता जा रहा है और मानव

जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक पर्यावरण की गुणवत्ता को भी खतरा उत्पन्न हो गया है जनसंख्या की बढ़ती दर और प्राकृतिक संसाधनों का तेजी से ह्रास और गुणवत्ता में गिरावट ने टिकाऊ खेती को वर्तमान समय में महत्वपूर्ण बना दिया है। भविष्य की पीढ़ियों के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को सहेज कर रखते हुए वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने के लिए टिकाऊ खेती का विकल्प पर्यावरण नियोजकों द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता प्राप्त कर रहा है।

संधारणीय खेती का आधार क्या है?

फसल प्रणाली में अलग अलग फसल जैसे धान्य, दलहन, तिलहन और रेशा फ सलों के समावेश से प्रति इकाई लागत को कम किया जा सकता है। साथ ही, घरेलू आवश्यकता पूर्ति के साथ-साथ मृदा स्वास्थय का संरक्षण होता है। उचित जल प्रबंधन व्यवस्था के साथ उत्पादन घटकों की उपयोग दक्षता को बढ़ाया जा सकता है। नत्रजन, फास्फोरस और पोटाश का उचित अनुपात (4:2:1) में उपयोग और जरूरत होने पर सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी प्रयोग करना। ताकि, पोषक तत्वों की उपलब्धता में संतुलन बना रहे। जैविक खाद जैसे हरी खाद, गोबर खाद, वर्मी कम्पोस्ट और जैव उर्वरक राइजोबियम आदि को रासायनिक उर्वरकों के साथ सही अनुपात में प्रयोग किये जाने से फसल उत्पादकता में बढ़ोतरी के साथ मृदा स्वास्थ्य में भी भारी सुधार होता है। कीट-रोग का एकीकृत नियंत्रण और उन्नत शस्य क्रियाओं को अपनाया जाता है।

संधारणीय खेती के लाभ बताएं?

भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है। मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों को संतुलित और दीर्घकालीन उपयोगी बनाती है। मृदा में लाभकारी सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती है। भूमिगत जल स्तर को बनाये रखने में सहायक है। रसायनों का कम प्रयोग होने से कृषि लागत में कमी होती है और प्रदूषण को भी नियंत्रित करती है। प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग होता है। फ सल उत्पादों की गुणवत्ता को बनाए रखने में सहायक है । खराब गुणवत्ता वाले फसल उत्पादों के सेवन से होने वाली गंभीर बीमारियों से बचाव होता है। कृषि कार्यों को आर्थिक रूप से स्वपोषित बनाती है। ईंधन की आवश्यकता की पूर्ति करती है।

टिकाऊ खेती से आय बढ़ोत्तरी संभव है।

टिकाऊ खेती में फसलों का विविधिकरण किया जाता है। इससे आय में बढ़ोत्तरी देखने को मिलती है। किसान फसल के साथ पशुपालन, मत्स्य, पोल्ट्री, वानिकी, मधुमक्खीपालन, बागवानी, मशरुम, रेशम, सब्जियाँ, औषधीय, सुगन्धित पौधे और फूलों की खेती करें। ऊर्जा, भूमि, जल, मानव शक्ति (श्रम) और प्राकृतिक संसाधनों को व्यवस्थित ढ़ंग से उपयोग करना होगा।

अध्यात्म

अपने लक्ष्य पर अडिग रहो, जरूर मिलेगी सफलता

राजमहल के सुंदर बगीचे में मेले सा आयोजन हुआ। कहीं गीत संगीत की महफिल सजी थी तो कहीं खाने पीने का सामान था। कई खेल भी यहां हो रहे थे। राजा से मिलने के लिए लोगों की भारी भीड़ आई थी, लेकिन कितने ही लोग नाच-गाने में अटक गए तो कितने ही खाने पीने में व्यस्त हो गए। कई लोग खेलों में ही खो गए। समय बीतने लगा, इस बीच एक व्यक्ति ऐसा भी था, जिसने मेले की किसी भी चीज की ओर देखा तक नहीं।

एक संपन्न राज्य के राजा के कोई संतान नहीं थी। वह वृद्ध होने लगा था, उसे अपने उत्तराधिकारी को लेकर चिंता सताने लगी। योग्य उत्तराधिकारी की खोज के लिए राजा को एक विचार आया। राजा ने अगले ही दिन पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि जो व्यक्ति आज शाम को मुझसे आकर मिलेगा, उसे राज्य का एक हिस्सा दिया जाएगा। राजा के इस निर्णय पर मंत्रियों ने कहा कि महाराज ऐसे तो कई लोग आपसे मिलने आ जाएंगे और यदि आपने सभी को उनका भाग दे दिया तो पूरे राज्य के टुकड़े हो जाएंगे। यह सुनकर राजा ने कहा कि आप लोग बस देखते रहें कि क्या हो रहा है।

शाम को राजमहल के सुंदर बगीचे में मेले सा आयोजन हुआ। कहीं गीत संगीत की महफिल सजी थी तो कहीं खाने पीने का सामान था। कई खेल भी यहां हो रहे थे। राजा से मिलने के लिए लोगों की भारी भीड़ आई थी। लेकिन, कितने ही लोग नाच-गाने में अटक गए तो कितने ही खाने पीने में व्यस्त हो गए। कई लोग खेलों में ही खो गए। समय बीतने लगा, इस बीच एक व्यक्ति ऐसा भी था, जिसने मेले की किसी भी चीज की ओर देखा तक नहीं। वह मन में सिर्फ राजा से मिलने की ही बात ठानकर आया था।

वह बगीचा पार कर राजमहल के दरवाजे पर पहुंच गया। पहरेदारों ने उसे रोका। लेकिन, वह उन्हें धक्का देकर सीधे राजमहल में आ गया। जैसे ही वह अंदर पहुंचा तो राजा ही उसके सामने आ गए। राजा ने कहा कि कोई तो ऐसा मिला जो किसी भी प्रलोभन में फंसे बिना अपने लक्ष्य तक पहुंच सका। तुम ही मेरे उत्तराधिकारी बनोगे। सफलता उसी को मिलती है जिसका लक्ष्य तय होता है और अपने लक्ष्य पर जो अडिग रहता है।

प्रदेश में किसान कानून

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

किसानों के लिए प्रदेश में पालित काश्तकारी नियम, अधिनियम, धारा, उपधारा, विच्छेद, शब्दावली परिभाषा, न्यायिक अपीलीय अधिकार से जुड़ी जानकारी दी जा रही है। कॉलम में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-उपधारा से जुड़ी जानकारी इस प्रकार है।

1. अधिकार घोषणा-जोहड़ पायतान-सार्वजनिक.- प्रत्यर्थीगण के पिता ने राज्य सरकार के विरुद्ध एक वाद अधिकार घोषणा, राजस्व अभिलेख में शुद्धि एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि उनके कब्जे काश्त की रही है तथा 1966 में आवंटित की गई थी। परन्तु विवादित भूमि वादीगण के खातेदारी की भूमि नहीं है वरन् जोहड़ पायतान दर्ज है। भू प्रबन्ध विभाग राजस्व अभिलेख की प्रविष्टियों में परिवर्तन नहीं कर सकता है। विवादित भूमि जोहड़ पायतान (जल ग्रहण क्षेत्र) है। गाँव वालों के सामान्य उपयोग में आने वाली भूमि है और ऐसी भूमि में जो सार्वजनिक उपयोग की है, में धारा 16 के तहत खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं हो सकते है।

2. खातेदारी-कब्जा-दस्तावेजों के खण्डन का अवसर.- अपीलांट/वादी ने विचारण न्यायालय के धारा 88 और 188 के तहत खातेदारी का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय के आदेश की पुष्टि की।

अपीलांट ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 27 के तहत खसरा गिरदावरी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की। अभिनिर्धारित खसरा गिरदावरी संवत् 2012 से वादी का कब्जा वादग्रस्त आराजी पर प्रमाणित होता है। न्यायहित में प्रतिवादीगण को उक्त दस्तावेजों के खण्डन का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है। अपील आंशिक रूप से स्वीकार।

आदेश 41 नियम 27 के प्रार्थना पत्र पर द्वितीय अपील के निर्णय के साथ ही निस्तारण को विधिक मानते हुए प्रकरण पुन: सुनवायी कर निर्णय किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किए जाने के निर्देश पर अपनी सहमति प्रदान की।

3. आरएए का आदेश अलील विरुद्ध- क्षेत्राधिकार.- धारा 235 के अवलोकन से स्पष्ट है कि इसके अनुसार सक्षम न्यायालय को ही वाद को मुंतकिल किया जा सकता है। अधिनियम की तृतीय अनुसूची के कॉलम 7 के अनुसार जो सक्षम न्यायालय की सूची है उसके अनुसार अधिनियम की धारा 88, 89 और 188 के वादपत्र को निस्पादित करने हेतु सहायक कलेक्टर न्यायालय ही सक्षम न्यायालय है अतिरिक्त कलक्टर को अधिनियम की धारा 88, 89 और 188 के तहत उपखण्ड अधिकारी के यहां जो वादपत्र प्रस्तुत किया गया था उसे निस्तारित करने हेतु अतिरिक्त कलक्टर सक्षम न्यायालय नहीं है। जिला कलक्टर द्वारा हस्तगत प्रकरण में उनके सक्षम प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर सक्षम उपखण्ड अधिकारी अथवा सहायक कलक्टर को प्रकरण को निर्णय हेतु प्रेषित करना चाहिए था। प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अतिरिक्त कलक्टर के न्यायालय को प्रेषित करने में विद्वान जिला कलक्टर के स्तर पर क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि की गई है।

क्रमशः

कृषि विपणन में व्यापक सुधार

नजरिया

भारत आज 1.35 अरब लोगों का देश है। 2017 के संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या अनुमान के मुताबिक, भारत 2024 तक चीन की आबादी को पीछे छोड़ सकता है और 2030 में 1.5 अरब आबादी के साथ दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला राष्ट्र बन सकता है। करीब दो तिहाई भारतीय 35 वर्ष से कम उम्र के हैं। पिछले दो दशकों से भारत की जीडीपी लगभग सात फीसदी सालाना की दर से बढ़ रही है और कम से कम एक दशक और यह गति बरकरार रहने की संभावना है। जनसंख्या वृद्धि धीरे-धीरे घटकर अब 1.1 फीसदी रह गई है और यही रफ्तार जारी रही, तो अगले दशक में भारत में प्रति व्यक्ति आय सालाना छह फीसदी की दर से बढ़ने की संभावना है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस (एनएसएसओ) द्वारा कराए गए 2011 के खपत व्यय सर्वेक्षण से पता चला है कि एक औसत भारतीय परिवार अपने मासिक खर्च का लगभग 45 फीसदी भोजन पर खर्च करता है, इसका मतलब यह हुआ कि भारत में खाद्य की मांग आने वाले वर्षों में बढ़ने वाली है। इससे एक बुनियादी सवाल पैदा होता है कि क्या भारत खुद अपने लिए खाद्य उत्पादन कर सकता है अथवा एक बड़ा खाद्य आयातक बनेगा। गंभीर है। क्योंकि, भारत में खेती योग्य भूमि सीमित है (शुद्ध बुवाई क्षेत्र करीब 14 करोड़ हैक्टयर) और इसका भू-जल स्तर निरंतर घट रहा है, साल में लगभग एक मीटर की दर से भू-जल स्तर में गिरावट आ रही है। जलवायु परिवर्तन की भविष्यवाणी बढ़ते तापमान और सूखे की अधिक आवृत्ति और तीव्रता का संकेत देती है। ऐतिहासिक रूप से भारत के लिए अपनी आबादी का पेट भरना कठिन चुनौती रहा है। लेकिन, आज भारत न केवल प्रमुख खाद्यों के उत्पादन में आत्मनिर्भर है, बल्कि निर्यातक भी है। वर्ष 2012-13 से 2014-15 के बीच भारत ने 6.3 करोड़ टन अनाज का निर्यात किया और आज भारत चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है। दूध भारत का सबसे बड़ा कृषि उत्पाद है। मूल्य के संदर्भ में इसका उत्पादन (वर्ष 2017-18 में 17.7 करोड़ टन) संयुक्त रूप से चावल और गेहूं से अधिक है। 1970 और 1980 के दशक के दौरान वर्गीज कुरियन के मार्गदर्शन में श्वेत क्रांति हुई। उसके बाद भारत ने कृषि क्षेत्र में कई क्रांतियाँ की। मत्स्य क्षेत्र में नीली क्रांति, पॉल्ट्री क्षेत्र में लाल क्रांति, फल-सब्जी क्षेत्र में स्वर्णिम क्रांति और कपास के क्षेत्र में जीन क्रांति। प्रौद्योगिकी और संस्थानों में नवाचार शुरू करके की गई इन कृषि क्रांतियों ने भारत को कृषि उत्पादन का निर्यातक बना दिया। लेकिन, एक चीज जो इस विकासवादी प्रक्रिया में ज्यादा सामने नहीं आई, वह है किसानों के प्रोत्साहन का मुद्दा। आज जबकि बहुत से मुद्दों को सुलझा लिया गया है, किसानों की आय का मुद्दा वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भी ज्वलंत है। सत्तारूढ़ भाजपा ने 2019 के चुनावी घोषणा पत्र में 2022-23 तक किसानों की आय दोगुना करने का वादा किया है। इसने 2018-19 में लगभग 23 प्रमुख फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा करके कृषि संकट को दूर करने की कोशिश की है। लेकिन, बड़े पैमाने पर सरकारी खरीद तंत्र की कमी के कारण अधिकांश फसलों की बाजार कीमत घोषित एमएसपी से 10 से 30 प्रतिशत नीचे रह गई। राजनीतिक असंतोष को देखते हुए भाजपा ने किसानों के खाते में नकद आय हस्तांतरण का वादा किया। जिसकी लागत करीब 87,600 करोड़ रुपए हो सकती है। हालांकि, यह किसानों की आय में मात्र 5 फीसदी का योगदान देगा। 2022-23 तक किसानों की आय दोगुना करने के लिए कृषि विपणन में व्यापक सुधार की आवश्यकता होगी। भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था ऐसी रही है कि जब भी घरेलू कीमतें बढ़ी हैं, चाहे वह प्याज हो, गेहूं हो अथवा चावल, तो कृषि उत्पादों के निर्यात को प्रतिबंधित किया गया है। निजी क्षेत्र को बड़ा स्टॉक रखने की अनुमति नहीं है और कभी-कभी अंतर्राज्यीय गतिविधियों को 1955 के आवश्यक वस्तु अधिनियम के जरिये प्रतिबंधित कर दिया जाता है। इसने निवेश की कमी के कारण निजी क्षेत्र द्वारा प्रभावी अखिल भारतीय मूल्य श्रृंखलाओं के निर्माण की अनुमति नहीं दी। इसके अलावा कृषि उपज और विपणन समिति (एपीएमसी) के माध्यम से कृषि विपणन को प्रतिबंधित किया गया। जो इन बाजारों के माध्यम से ही किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए बाध्य करता है। इन बाजारों में कमीशन एजेंटों द्वारा धांधली होती है। जो, मूल्य श्रृंखला में उपभोक्ताओं से ज्यादा रुपये लेते हैं। इन प्रतिबंधात्मक व्यापार और विपणन नीतियों के परिणामस्वरूप, भारत के किसानों को भारी अनुदान मिलने के बावजूद बहुत कम लाभ मिलता है। इससे स्पष्ट है कि भारत के खाद्य और कृषि नीतियों में उपभोक्ताओं के प्रति काफी पक्षपात किया जाता है, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ता है। इन शोध निष्कर्षों का सबक यह है कि भारत अगर अपनी नीतिगत संरचना में सुधार कर सकता है, तो कम से कम किसानों को उपभोक्ताओं के साथ बराबरी का हक सुनिश्चित करना होगा, उसके बाद ही किसानों को बेहतर प्रोत्साहन और लाभ मिल सकता है। वह नई प्रौद्योगिकी अपना सकते हैं, पैदावार बढ़ा सकते हैं और भारत को अधिक प्रतिस्पर्धी बना सकते हैं। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका मौलिक रूप से ईसीए, एपीएमसी अधिनियम, निर्यात नीति आदि में सुधार करना होगा। अगर भारत ऐसा कर सकता है, तो वह न केवल अपनी आबादी का पेट भर सकता है, बल्कि निर्यात के लिए अतिरिक्त अनाज भी पैदा कर सकता है। इस लोकसभा चुनाव में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी कृषि विपणन में सुधार के साथ-साथ आबादी के निचले 20 फीसदी हिस्से को प्रत्यक्ष आय सहायता देने का वादा किया है। हालांकि, कृषि विपणन सुधार पर भाजपा का रुख स्पष्ट नहीं है। लेकिन, उसने भी किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता देने का वादा किया है। इस लोकसभा चुनाव के बाद चाहे कोई भी पार्टी सत्ता में आए, एक चीज तो स्पष्ट है कि भारत किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता देने के लिए तैयार है और इससे भारत को कम से कम 2030 तक अपनी आबादी को अच्छी तरह से खिलाने में मदद मिल सकती है।

- अशोक गुलाटी

शिक्षा का मुख्य उद्देश्य चरित्र निर्माण-डॉ. सिंह

युवा महोत्सव गोरबंद-2019

बीकानेर (कास)। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के पूर्व कुलपति डॉ. बलराज सिंह ने कहा कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य चरित्र निर्माण है। शिक्षक-विद्यार्थी इसे समझें और इसके मुताबिक शिक्षार्जन करें-कराएं। डॉ. सिंह एसकेआरएयू में आयोजित युवा महोत्सव गोरबंद को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा छिपी प्रतिभा को निखारने में 'गोरबंद' जैसे आयोजन प्रभावी भूमिका निभाते हैं। ऐसे कार्यक्रम समय-समय पर हों और विद्यार्थी, संकोच की भावना को छोड़कर इनमें भागीदारी निभाएं। ब्रह्म गायत्री सेवा आश्रम के अधिष्ठाता दाताश्री रामेश्वरानंद महाराज ने विद्यार्थियों को सफलता के पांच नियम और लक्षण बताए। उन्होंने कहा विद्यार्थी आत्ममंथन-आत्मावलोकन करते हुए अपनी कमियों को दूर करें और सफलता के पथ पर आगे बढें। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो.विष्णु शर्मा ने ने कहा कि आज, कृषि का परिदृश्य बदल रहा है। इस पर कृषि विद्यार्थी नजर रखें। उन्होंने विश्वविद्यालय में अगले 15 दिनों में 'प्लेसमेंट सेल' गठित करने की घोषणा की। कृषि महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ.आईपी सिंह, निदेशक छात्र कल्याण प्रो.वीर सिंह, केंद्रीय छात्र संघ अध्यक्ष सुनील कुमार बुरड़क, युवा कृषक संघ अध्यक्ष रवि जांदू ने भी विचार रखे।

विद्यार्थियों को पुरस्कार

कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय के पीजी-यूजी के टॉपर विद्यार्थियों, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और खेलकूद गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। वहीं इकतीस सौ रुपए का अमित गोदारा स्मृति अवार्ड, राजस्थान प्री-पीजी टेस्ट के प्रतिभावान विद्यार्थियों, बेस्ट एनसीसी विद्यार्थियों, इंटर हाउस कॉम्पीटिशन के विजेताओं और महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर आयोजित प्रदर्शनी के विजेताओं को पुरस्कार दिए गए।

देश-विदेश

ऑनलाइन होंगे केवीके

अयोध्या। नरेंद्रदेव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज अपने अधीन आने वाले सभी कृषि विज्ञान केन्द्रों और कृषि अनुसंधान केन्द्रों को ऑनलाइन करेगा। इन केंद्रों को वीडियो कांफ्रेंसिग की सुविधा से लैस करने की योजना है। इससे न सिर्फ केंद्रों की सतत मॉनीटरिग हो सकेंगी। बल्कि, कामकाज में तेजी आएगी। इसके लिए विवि ने 25 लाख रुपये का प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भिजवाया है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो.जेएस संधू ने बताया कि विवि से 23 कृषि विज्ञान केंद्र, 6 कृषि अनुसंधान केन्द्र और चार कृषि ज्ञान केन्द्र सम्बद्ध है।

किसान आयोग गठन को हरी झंड़ी

शिलांग। मेघालय सरकार ने किसानों की समस्याओं के समाधान और अध्ययन के लिए किसान आयोग के गठन को हरी झंडी दी है। उप-मुख्यमंत्री प्रेस्टन तीनसॉन्ग ने कहा कि कृषि विभाग द्वारा किसान आयोग के गठन के प्रस्ताव को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान कर दी।देश में अपनी तरह की पहली किसान संसद पिछले साल दिसंबर में यहां आयोजित हुई थी। इसमें राज्य में कृषि की स्थिति से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए किसानों के अलावा वैज्ञानिकों, नौकरशाहों आदि ने भाग लिया था। मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने उस समय किसानों की चिंताओं को दूर करने के लिए आयोग गठित करने की घोषणा की थी। उपमुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि सरकार 2020 को किसानों के वर्ष के रूप में मनाने की योजना बना रही है।

बनेंगे 10 हजार किचन गार्डन

रायपुर। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में परोसे जा रहे मध्यान्ह भोजन में हरी और ताजी सब्जियां अब स्कूल परिसर की बागवानी की ही उपलब्ध हो सकेंगी। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने फिलहाल दस हजार स्कूलों में किचन गार्डन विकसित करने के लिए बजट स्वीकृत कर दिया है। सत्र 2019-20 के लिए केंद्र सरकार ने 550 करोड़ रुपये स्वीकृत किया है। स्कूल परिसर में बच्चों को स्वच्छ पर्यावरण और हरियालीयुक्त वातावरण के साथ-साथ अब भूख मिटाने के लिए ही नहीं, बल्कि पोषण आधारित मेनू भी रिवाइज होने जा रहा है। स्कूलों में किचन गार्डन बनाने के लिए कृषि विभाग, बीज निगम, हार्टीकल्चर, मनरेगा और पंचायत विभाग एक संयुक्त अभियान के तहत काम करेगा।

3 जिलों में ग्रीन कवर

ओडिसा। फैनी तूफान से बागवानी फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार ने 188 करोड़ की पंचवर्षीय योजना तैयार की है। योजना के तहत चक्रवात प्रभावित जिले पुरी, भुवनेश्वर और कटक को ग्रीन कवर प्रदान करना है। मुख्य सचिव एपी पढ़ी के अनुसार 2019-20 में लगभग 130.5 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। जहां 80.5 लाख पेड़ों को वन विभाग लगाएगा । वहीं 50 लाख पौधे विभिन्न शिक्षण संस्थानों, औद्योगिक संपदा और अन्य निजी संपत्ति के मालिकों को अपने क्षेत्रों में पौधारोपण के लिए सौंपा जाएगा। आपको बता दें कि चक्रवाती तूफान फैनी ने 24,780 हैक्टयर क्षेत्र में बागवानी फसलों को नुकसान पहुंचाया है। योजना के तहत 18 लाख फल वाले पौधे लगाए जायेंगे।

ओलावृष्टि और बारिश से तापमान में आई कमी

अब बढ़ेगी बीटी की रफ्तार

जयपुर (कास)। प्रदेश में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम परिवर्तनशील बना हुआ है। इसके चलते प्रदेश में कहीं तेज गर्मी तो कहीं आंधी, बारिश और ओलावृष्टि हो रही है। पश्चिमी जिलों में बीते दिनों हुई ओलावृष्टि और मध्यम दर्जे की बारिश से दिन-रात के तापमान में कमी आई है। इससे बीटी कपास की बुवाई को रफ्तार मिली है। वहीं, जहां केवल बरसात हुई है, वहां जायद फसलों को भी फायदा पहुंचा है। आपको बता दें कि बरसात और ओलावृष्टि से पहले 42-45 डिग्री तापमान ने बीटी कपास बुवाई पर ब्रेक लगाए हुए थे। किसान तापमान ज्यादा रहने के चलते कपास बुवाई से कतरा रहे थे। किसानों का कहना था कि तेज गर्मी में बीटी कपास की बुवाई करने से बाद में सिंचाई की समस्या से दो चार होना पड़ता है। मानसून की भविष्वाणी को देखकर बुवाई करने से फसल में सिंचाई की मार नहीं रहती है।

गौरतलब है कि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ जिले के किसानों को नहरी पानी मिलना शुरू हो गया है। इससे इस साल कपास बुवाई का क्षेत्रफल बढ़ने की उम्मीद है। किसान नहरी पानी को डिग्गी में संग्रहित कर रहे है। जानकारी के अनुसार श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, नागौर और जोधपुर जिले में उन जगहों पर कपास की बुवाई हुई है, जो सिंचित क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। कृषि आयुक्तालय के संयुक्त निदेशक (सांख्यिकी) बीएस राठौड़ ने बताया कि कपास की बुवाई पंजाब-हरियाणा में 1 से 15 मई तक किसान कर देते है। जबकि, यहां श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर प्रदेश के दूसरे जिलो में किसान मानसून की संभावित तिथि को देखते हुए कपास की बुवाई करते है। ताकि, फसल को प्राकृतिक सिंचाई मिलती रहे। आपको बता दें कि दक्षिणी राजस्थान में किसान कपास की बुवाई बरसात शुरू होने के साथ करते है। वहीं, जोधपुर, नागौर, पाली, अलवर, भरतपुर जिले के किसान चालू माह के अंतिम सप्ताह से बीटी कपास की बुवाई करना आरम्भ करते है। आपको बता दें कि पश्चिमी जिले बाड़मेर में ओलावृष्टि हुई है। वहीं, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, जोधपुर, सीकर आदि जिलों में बरसात हुई है।

2.74 हैक्टयर में कपास बुवाई

प्रदेश में कपास की बुवाई 6 लाख हैक्टयर के मुकाबले 2.74 लाख हैक्टयर क्षेत्र में हो चुकी है। इनमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और अलवर जिले में अच्छी बुवाई दर्ज हुई है। तापमान में आई कमी के बाद जोधपुर, नागौर, पाली और भरतपुर जिले में भी कपास बुवाई ने रफ्तार पकड़ ली है। जानकारी के अनुसार इस वर्ष भी किसान बीटी कपास की बुवाई को प्राथमिकता दे रहे है। नरमा और अमेरिकन कपास की बुवाई श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में होती है। लेकिन, दोनो ही जिलो में कपास की इन किस्मों का क्षेत्रफल इस बार कम रहने की संभावना है।

जायद की अच्छी बुवाई

नजर डाले जायद फसलों की बुवाई पर तो मूंग की बुवाई 3528 हैक्टयर में, उड़द की 79 हैक्टयर में, मूंगफली की 3787 हैक्टयर में, ग्वार की 46 हैक्टयर और बाजरा और ज्वार की बुवाई 30720 हैक्टयर में हुई है। इसी तरह जायद सब्जियों की बुवाई 18 हजार हैक्टयर से ज्यादा हुई है।

बीजोत्पादन में आबूसर केवीके देश में अग्रणी

झुंझुनू। कृषि विज्ञान केन्द्र, आबूसर बीजोत्पादन के मामले में देश का अग्रणी केन्द्र बनकर उभरा है। केन्द्र के अध्यक्ष ड़ॉ. दयानंद ने बताया कि केंद्र ने अपने मुख्य कार्य किसानों को प्रशिक्षण देने, प्रदर्शन और दूसरी प्रसार गतिविधियों के ट्रेंड से हटकर गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन के लिए कदम बढ़ाए और सफलता भी मिली है। उन्होंने बताया कि कि वर्ष 2018-19 में कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से अब तक का सर्वाधिक बीज का उत्पादन किया है। जो प्रदेश के ही नहीं वरन देश के सात सौ के करीब कृषि विज्ञान केंद्र में सबसे अव्वल है। केंद्र पर खरीफ फसल में मूंग, ग्वार , चंवला और रबी फसलों में गेहूं, जौ, चना, सरसों, मैथी के बीज का उत्पादन किया जाता है।

उन्होंने बताया कि रबी 2018-19 में मौसम की अनुकूलता, उन्नत किस्में और केंद्र के वैज्ञानिकों की मेहनत का ही नतीजा है कि अब तक सबसे रेकॉर्ड 1657.73 क्विंटल गुणवत्तापूर्ण बीज का उत्पादन हुआ है। यह बीज आगामी रबी मौसम में जिले तथा आस-पास के किसानों को उपलब्ध करवाया जायेगा। आपको बता दें कि बीज उत्पादन और रिकॉर्ड आय के चलते वर्ष 2007 में इस केन्द्र को राष्ट्रीय स्तर का बेस्ट कृषि विज्ञान केंद्र अवार्ड मिल चुका है।

कृषि विभाग ने जारी किए लक्ष्य

163.73 लाख हैक्टयर में होगी खरीफ बुवाई

जयपुर (कास)। राज्य सरकार ने इस वर्ष खरीफ के लिए 163.73 लाख हैक्टयर क्षेत्र में फसल बुवाई का लक्ष्य रखा है। साथ ही, फसल उत्पादन के अनुमान भी तय किए है। खरीफ खाद्यान्न फसलों का उत्पादन लक्ष्य 72.30 लाख एमटी, दलहन के लिए 20.23 लाख एमटी और तिलहनी फसलों के लिए 31.05 लाख एमटी उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आपको बता दें कि मौसम विभाग द्वारा इस साल मानसून सामान्य रहने के पूर्वानुमानों के चलते कृषि विभाग ने फसल बुवाई के क्षेत्रफल में वृद्धि की है। वर्ष 2018-19 में खरीफ फसलों की बुवाई के लिए विभाग ने 161.61 लाख हैक्टयर का लक्ष्य रखा था। इस साल सकल बुवाई लक्ष्य में 2.12 लाख हैक्टयर की बढोत्तरी की गई है। अब देखना यह है कि मानसून किसानों का कितना साथ देता है। क्योंकि, निजी एंजेसी स्काईमेट ने अपने पूर्वानुमान में इस साल मानसून 7 फीसदी कम रहने का अंदेशा जताया है। आपको बता दें कि प्रदेश में जून माह के अंतिम सप्ताह से किसान खरीफ फसलों की बुवाई करना शुरू कर देते है। क्योंकि, मध्य जून तक प्रदेश में प्री-मानसून शॉवर शुरू हो जाता है। आपको बता दें कि खरीफ में बाजरा, मक्का, मूंगफली, उड़द, मूंग, मोठ सहित दूसरी फसलों की अच्छी बुवाई प्रदेश में होती है।

यह रखे लक्ष्य

फसल	लक्ष्य	फसल	लक्ष्य
धान	1.80	ज्वार	6
बाजरा	45	मक्का	9.20
मूंग	20	मोठ	11
उड़द	7	चंवला	0.80
अरहर	0.10	मूंगफली	6.50
तिल	4	सोयाबीन	10.50
अरंड़ी	1.20	गन्ना	0.05
कपास	6	ग्वार	30
अन्य	4.40	(लक्ष्य लाख हैक्टयर में)	

मांग कम, बीज ज्यादा

फसल बुवाई लक्ष्य तय होने के साथ ही, कृषि विभाग ने आदान व्यवस्था की नब्ज नापना शुरू कर दिया है। विभागीय अधिकारियों की माने तो इस साल किसानों को कृषि आदान उपलब्धता में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि, इस साल अनुमानित बीज मांग की तुलना में बीजों की उपलब्धता ज्यादा है। संयुक्त निदेशक कृषि (आदान) डॉ. रामगोपाल शर्मा ने बताया कि खरीफ के लिए 8.55 लाख क्विंटल फसली बीजों की जरूरत है। जबकि, बीजों की उपलब्धता 9.13 लाख क्विंटल के करीब है। इसी तरह उर्वरक की मांग का अनुमान लगाया गया है। यूरिया के लिए 7.50 लाख एमटी का अनुमान लगाया गया है। वर्तमान में 4 लाख एमटी यूरिया की उपलब्धता कृषि विभाग के पास है। डीएपी की मांग 4 लाख एमटी की तुलना में 2.5 लाख एमटी की उपलब्धता वर्तमान में है। वहीं, सिंगल सुपर फास्फेट की मांग 1.70 लाख एमटी रहने का अंदेशा है। वर्तमान में एसएसपी की उपलब्धता 80 हजार एमटी के करीब है। इसके अलावा दूसरे उर्वरकों की मांग 43 हजार एमटी रहने का अनुमान है। आपको बता दें कि प्रदेश में खरीफ के लिए बीज की मांग 13-14 लाख क्विंटल की रहती है।

अनुसंधान सलाहकार समिति की बैठक

कृषि वैज्ञानिकों ने बताया बीजीय मसालों का भविष्य

अजमेर (कास)। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र पर दो दिवसीय अनुसंधान सलाहकार समिति की दूसरी वार्षिक बैठक नवसारी कृषि विश्वविद्यालय गुजरात के पूर्व कुलपति डॉ. बीएस चुंडावत की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में बीजीय मसाला फसलों में भविष्य में आने वाली परेशानियां और वर्तमान स्थिति के साथ-साथ नवीन अनुसंधान परियोजनाओं पर चर्चा की गई। कृषि वैज्ञानिकों ने गुणवत्ता पूर्ण बीजीय मसालों का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया। साथ ही, किसानों तक नवीन उत्पादन प्रौद्योगिकी के प्रसार और नई किस्मों के बीज उपलब्ध करवाने की आवश्यकता जताई गई।

बैठक के दौरान डॉ. कृष्ण कांत द्वारा कार्यवाही रिपोर्ट (एटीआर) प्रस्तुत की गई। अध्यक्ष डॉ. बीएस चुंडावत ने बीजीय मसाला उत्पादन के क्षेत्र में प्रगति पर चर्चा की। केंद्र के निदेशक डॉ. गोपाल लाल ने बताया कि संस्थान द्वारा विगत वर्षों में कुल सात प्रजातियों का नोटीफिकेशन केन्द्रीय किस्म विमोचन समिति नई दिल्ली द्वारा किया गया है, जिसमें अजमेर धनिया, सौंफ, मैथी, अजवायन-93 प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त दो किस्मों का चयन अखिल भारतीय समन्वित मसाला अनुसंधान परियोजना की कार्यशाला-2018 में हुआ है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के सहायक महानिदेशक डॉ. टी. जानकीराम ने बीजीय मसालों और उद्यानिकी फसलों में राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे अनुसंधान के बारे में बताया।

सलाहकार समिति यह

आईसीएआर द्वारा गठित अनुसंधान सलाहकार समिति का अध्यक्ष और नवसारी कृषि विश्वविद्यालय गुजरात के पूर्व कुलपति डॉ. बीएस चुंडावत को बन,ाया गया है। वहीं, आईसीएआर के सहायक महानिदेशक डॉ. टी. जानकीराम, डॉ. अमरेन्द्र रेड्डी, डॉ. के.वी. रमन्ना, डॉ. राम अवतार शर्मा, डॉ. आई.एस. सिंह, डॉ. वी. श्रीनिवास, डॉ. गोपाल लाल और डॉ. कृष्ण कांत, सदस्य सचिव बनाया गया है।

उत्पादन में 80 फीसदी बढ़ोत्तरी

केन्द्र के निदेशक गोपाल लाल ने बताया कि दशक में बीजीय मसालों के उत्पादन में 80 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और उत्पादकता 10 क्विंटल प्रति हैक्टयर से अधिक पहुंच गई है। इसी अवधि में बीजीय मसालों का कुल निर्यात लगभग 5 गुना बढ़ गया है। संस्थान की स्थापना से अब तक कुल 23 प्रजातियों का विकास किया जा चुका है। संस्थान द्वारा जैव नियंत्रकों, जैव उर्वरकों, वानस्पतिक कीट नाशकों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के साथ बीजीय मसाला उत्पादन तथा जैविक बीजीय मसाला उत्पादन पर विशेष अनुसंधान कार्य किया जा रहा है।

अब मशीन से होगी गन्ने की रोपाई

नई दिल्ली। गन्ने की खेती करने वाले किसानों के लिए कृषि अभियांत्रिकी के वैज्ञानिकों ने मल्टीपल मशीन तैयार की है। एक ही मशीन से किसान गन्ने की रोपाई भी कर सकेगा। साथ ही, खाद और कीटनाशक का छिड़काव के लिए भी इस मशीन का उपयोग कर सकेगा। वैज्ञानिको ने इस मशीन को शुगर केन प्लाटंर नाम दिया है। कृषि वैज्ञानिकों का दावा है कि यह आठ घंटे में करीब ढाई एकड़ में गन्ना पौध की रोपाई कर सकती है। इस काम में तीन मजदूरों से ही काम चल सकता है। यही नहीं 92 क्विंटल गन्ने की बचत भी होगी। फसल स्वस्थ रहने का भी दावा किया गया है। इससे उत्पादन भी बढ़ सकता है, क्योंकि किसान स्वस्थ पौध की ही रोपाई कर सकेंगे। मशीन की कीमत लगभग 2 लाख रुपए की है।

25 दिन में तैयार होगी गन्ने की पौध

वैज्ञानिकों के अनुसार गन्ने की आंख काट ली जाती है। परंपरागत विधि से किसान प्रति हैक्टयर करीब 100 क्विंटल गन्ने का बीज खेत में डालते हैं। नई विधि से केवल 8 क्विंटल गन्ने से काम चल जाएगा। इस विधि में किसान 30 क्विंटल गन्ना लेते हैं और 8 क्विंटल आंखें ही पौध के लिए निकालते हैं। शेष 22 क्विंटल गन्ना किसान शुगर मिल में बेच सकते हैं। करीब 20 से 25 दिन में गन्ने की पौध तैयार हो जाती है। इसे मशीन के साथ किसान खेत में रोपाई कर सकते हैं।

पौधरोपण मशीन पर लगी होती है ट्रे

पौधरोपण मशीन को ट्रैक्टर के पीछे लगा एक व्यक्ति चलाता है, जबकि दो व्यक्ति मशीन पर बैठते हैं। यह दोनों ट्रे में तैयार पौध को रखते रहते हैं और मशीन ट्रे से पौध को उठा खेत में रोपाई कर देती है। इससे पहले खेत को अच्छी तरह तैयार किया जाता है और जुताई कर मिट्टी बारीक की जाती है।

इंटरक्रॉपिंग में भी मिलेगा फायदा

मशीन को जितना चाहे, उतनी दूरी पर सेट कर सकते हैं। इससे गन्ने के साथ-साथ इंटरक्रापिंग यानी अंतर-वर्ती फसल लेने में कठिनाई नहीं होती। किसान करीब 20 प्रकार की फसलें गन्ने के साथ आसानी से ले सकते हैं। फसल के हिसाब से गन्ने की पौध की रोपाई खेत में की जा सकती है।

मशीन से रोपाई में ये होती है बचत

परंपरागत तरीके से गन्ने की बिजाई करने से प्रति हैक्टयर करीब 10 मजदूरों की जरूरत होती है। लेकिन, मशीन से रोपाई करने में तीन मजदूरों से ही काम चल जाता है। एक हैक्टयर गन्ने की पौध की रोपाई 8 घंटे में ट्रैक्टर से की जा सकती है। फसल की आवक 20 से 25 दिन पहले हो जाती है।

92 क्विंटल गन्ना भी बचता है

बड चिपिंग से गन्ने की काफी बचत होती है। गन्ने से आंख काटे जाने के बाद किसान के पास जो गन्ना बचता है, उसे वह शुगर मिल में बेच सकता है। अमूमन जब किसान 100 क्विंटल तक गन्ने का बीज खेत में डालते हैं तो 90 फीसदी से अधिक गन्ना बेकार चला जाता है।

कार्यक्रम | कृषि महाविद्यालय फतेहपुर का वार्षिकोत्सव

देश में कृषि का भविष्य उज्जवल- डॉ. शर्मा

जयपुर (कास)। एसकेएन कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. जेपी शर्मा ने कहा कि जिस प्रकार से स्कूलों में गणित, भौतिक विज्ञान और रसायन शास्त्र की पढाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ठीक ,उसी प्रकार से कृषि शिक्षा पर भी जोर दिये जाने की जरूरत है। जिससे नयी पीढ़ी में कृषि के प्रति लगाव उत्पन्न हो सके। उन्होंने कहा कि देश में कृषि शिक्षा का भविष्य उज्जवल है। क्योंकि, यहां 70 फीसदी आबादी कृषि से जुड़ी है। साथ ही, जीडीपी में कृषि क्षेत्र की 18 फीसदी भागीदारी है। ऐसे में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को अपने भविष्य की चिंता छोड़ देना चाहिए। क्योंकि, आगामी समय कृषि और किसान का है। कुलपति शर्मा कृषि महाविद्यालय फतेहपुर के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम आगाज को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विश्व बैंक से लेकर विकसित और विकासशील देश कृषि विकास और किसान की आर्थिक समृद्धता पर फोकस कर रहे है। ऐसे में कृषि शिक्षा हासिल करने वालों के लिए रोजगार की कमी नहीं है। आकाशवाणी केन्द्र जयपुर के कार्यवाहक निदेशक ब्रह्मप्रकाश ने कहा कि

कृषि क्षेत्र के विकास में सूचना और संचार तकनीक का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आकाशवाणी केन्द्र निरंतर किसान और वैज्ञानिकों के बीच कड़ी बनकर किसानों की समस्याओं के समाधान विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से बता रहा है। विश्वविद्यालय के एडीएसडब्ल्यू डॉ. हरफूल सिंह ने कहा कि युवाओं को कृषि से जोड़ने के लिए सामाजिक सोच में बदलाव लाना होगा। उन्होंने सवाल किया किया वर्ष 2050 तक देश की आबादी 1.6 अरब हो जायेगी और कृषि को लेकर ऐसी ही सोच बनी रही तो इतनी बड़ी आबादी की खाद्य और पोषण सुरक्षा का क्या होगा। कार्यक्रम में महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ. जेएस मिश्र ने महाविद्यालय की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। समारोह को फैकल्टी चेयरमैन जीएस बागंरवा, रजिस्ट्रार एस मुखर्जी, निदेशक एसओडी डॉ. रविन्द्र पालीवाल ने भी सम्बोधित किया।

विद्यार्थियों का सम्मान

समारोह के दौरान शैक्षणिक, खेलकूल, सांस्कृतिक और दूसरी गतिविधियों में उत्कृष्ट करने वाले विद्यार्थियों को कुलपति जेपी शर्मा ने प्रशस्ती पत्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस मौके पर महाविद्यालय के छात्र- छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक नृत्यों की प्रस्तुति भी दी गई।

कपास को स्वस्थ रखेगी छाछ

तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय का शोध

नई दिल्ली। वैज्ञानिकों ने कपास की फसल में लगने वाले स्ट्रीक वायरस से बचने के जैविक उपचार ढूंढ़ लिए हैं। तमिलनाडु कृषि विवि के वैज्ञानिकों ने पाया है कि कपास की फसल में तंबाकू स्ट्रीक वायरस से लड़ने के लिए बैसिलस एमिलोलिक फासिएंस नाम के राइजोबैक्टेरिया का उपयोग किया जा सकता है। आपको बता दें कि टीएसवी वायरस कपास की फसल में कीटों के माध्यम से पौधों को संक्रमित करता है। ज्यादातर किसान यह समझ ही नहीं पाते और इसके नियंत्रण के लिए कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। इसलिए वैज्ञानिक इसके नियंत्रण के लिए पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन विधि की तलाश शुरू की। कुछ अध्ययन के जरिए कपास के पत्ते के कर्ल, कुकुम्बर मोजेक वायरस और टोबेक मोजेक वायरस की जानाकरी मिली। इससे जानकारी लेते हुए शोधकर्तओं ने राइजोफेरिक और इंडोफाइटिक बैक्टिरिया को इकट्ठा किया। उसके बाद बैक्टीरिया के कल्चर के माध्यम से उनकी एंटीवायरल जानकारी का आंकलन किया। उन्होंने पाया कि बैसिलस एमिलोलिक फासिएंस नाम का एक राइजोबैक्टीरियम से बेहतर परिणाम मिले हैं।

इस तरह काम करता है यह बायोफार्मूलेशन : छाछ से तैयार फार्मूलेशन का वायरस के खिलाफ परीक्षण किया गया और प्रभावी पाया गया। इंसानों और पौधों में एंटीमाइक्रोबायल गतिविधि के लिए छाछ का प्रयोग होता आया है। इस नए अध्ययन में पाया गया है कि छाछ का बैसिलस फॉर्मूलेशन के संयोजन के साथ ज्यादा प्रभावी रहा है। वैज्ञानिकों ने जीवाणु संचरण के लिए छाछ को आधार बनाकर उपयोग किया। राइजोबैक्टीरियम कपास के राइजोस्फीयर और फाइलोप्लेन को उपनिवेशित करने और एंटी-माइक्रोबियल पेप्टाइड्स और फैटी एसिड का उत्पादन करने के लिए पाया गया था, जो वायरस को रोकता था।

अनदाता की चिट्ठी

पाठक। कद्दू की फसल ली है। पौधें की पत्तियां पीली पड़कर सूख रही है। साथ ही, किनारों पर धारियां भी नजर आ रही है। इसका क्या कारण है। उपाय बताये।

रामहेत गुर्जर, बकानी,झालावाड

हलधर टाइम्स। आपने फसल के जो लक्षण बतायें है वह कलिका नेक्रोसिस रोग के नजर आ रहे है। फसल में रोग का प्रकोप होने पर पौधे की पत्तियों के किनारे धारियां नजर आती है। जो बाद में पीली पड़कर नष्ट हो जाती है। रोग प्रबंधन के लिए रोगी पौधे को उखाड़कर खेत से अलग कर दे। इमिडाक्लोप्रिड 3-5 मिली प्रति 10 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर 2 बार छिड़काव करें। खेत के चारों ओर बाजरे की फसल उगायें, जिससे बीमारी कम आती है।

पाठक। मृदा सौर निर्जमीकरण क्या है। इससे क्या फायदा होता है।

नरसीराम, अजमेर

हलधर टाइम्स। मृदा सौर निर्जमीकरण सूत्रकृमि नियंत्रण की प्रभावशाली विधि है। इस विधि से सूत्रकृमियों के साथ-साथ विभिन्न कीट, रोगजनक कारक और खरपतवार की रोकथाम भी हो जाती है। इस विधि में गर्मियों में (जून) मृदा में सिंचाई करके 15-30 सेमी. गहरी जुताई करके उसे 4-5 सप्ताह तक पालीथीन शीट से ढ़क दिया जाता है, जिससे मृदा के उच्च तापक्रम द्वारा सूत्रकृमि नष्ट हो जाते है।

पाठक। पिछले साल मूंगफली की फसल ली थी। फलियां बनते समय पौधे तने के यहां से सूखकर नष्ट हो गए थे। इस साल इससे बचने के लिए क्या उपाय करूं।

जानकीलाल, श्रीडूंगरगढ़

हलधर टाइम्स। आपने जो लक्षण बतायें है वह मूंगफली में तनागलन रोग के प्रतीत हो रहे है। इस रोग से बचाव का एकमात्र रास्ता बीजोपचार और ग्रीष्मकालीन जुताई है। फसल में रोग का प्रकोप होने

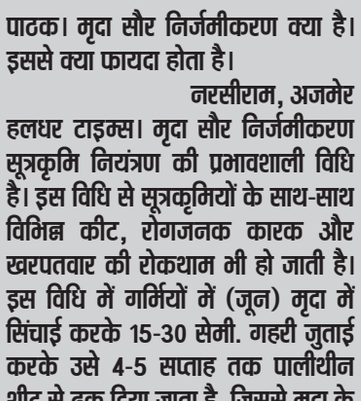

पर पौधे पीले पड़ने लगते है । मिट्टी की सतह से लगे पौधे के तने का भाग सूखने लगता है। जड़ों के पास मकड़ी के जाले जैसी सफेद रचना दिखाई पड़ती है। इससे उत्पादन पर भी विपरीत प्रभाव आता है। रोकथाम के लिए बीज को थायरम अथवा कार्बेण्डाजिम 3 ग्राम प्रति किग्रा की बीज से उपचारित करके बुवाई करें।

पाठक। खरीफ में अगेती मक्का की बुवाई करना चाहता हूँ। इसके लिए प्रति हैक्टयर कितना बीज उपयुक्त रहेगा, बुवाई विधि भी बतावें।

कुंजीलाल पाटीदार, प्रतापगढ़

हलधर टाइम्स। मक्का बुवाई के लिए प्रति हैक्टयर 20 किलो बीज उपयुक्त रहता है। बुवाई में प्रमाणित बीज का ही उपयोग करें। मानसून वर्षा नहीं हो तो तैयार खेत में मानसून की संभावना को देखते हुए 2 से 3 दिन पूर्व मक्का की सूखी बुवाई करना लाभप्रद है। कतार से कतार की दूरी 60 सेमी. और पौधे से पौधे की दूरी 25 सेमी. रखे। बीज 6 सेमी. से अधिक गहरा नहीं बोये, इससे अंकुरण में सरलता रहती है। पौधे की संख्या 66000 प्रति हैक्टयर ही रखे।

पाठक। वर्षाकालीन बुवाई के लिए टमाटर की उपयुक्त किस्में कौन-कौनसी है। जानकारी देवें।

राधेश्याम, टोंक

हलधर टाइम्स। वर्षाकालीन टमाटर बुवाई के लिए जून माह में नर्सरी तैयार की जाती है। अच्छी किस्मों की बात करें तो एस-32, डीटी-10, पंत टी-1, पंजाब केसरी, सलेक्शन-152, सीओ-3, एचएस-101, एमटीएच -6, अर्का विकास, पंत बहार, रोमा, पूसा सलेक्शन-120, पूसा रूबी प्रमुख है। इनके अलावा अनेक निजी बीज कंपनियों की हाईब्रिड और रिसर्च किस्में भी बीज विक्रेताओं के यहां उपलब्ध है।

छोटे में सब कुछ

आम

सूटी मोल्ड रोग

यह रोग मधुआ कीट के आक्रमण से फैलता है। कीट का प्रकोप आम के पत्तों पर होता है। इससे आम के पत्तों पर काला रंग का धब्बा आने लगता है। धीरे-धीरे यह काला रंग चमकीला दिखने लगता है। पत्ता झुलसने लगता है।

नियंत्रण- इसके लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 एसएल 1 मिली प्रति लीटर पानी के साथ घोल बनाकर छिडकाव करे। दूसरा छिड़काव मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ घोल बनाकर छिडकाव करें। दो छिड़काव में एक सप्ताह का अंतर जरूर रखें।

टमाटर

हरा तेला

यह हरे रंग का नरम शरीर वाला हेलीकॉप्टर के आकार का कीट होता हैं। यह पत्ती की निचली सतह पर रहता हैं और हमेशा टेडा चलता है। फसल में इसके प्रकोप से किसान को उत्पादन में नुकसान उठाना पड़ता है।

प्रबंधन:- ऐसीफेट 75 एसपी 2 ग्राम अथवा एसीटामाप्रिड 20 एसपी 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिडकाव करे।

भिंडी

पीला मौजेक

पीला मौजेक बीमारी के प्रकोप से पत्ती की शिराये पीली पड़कर मोटी हो जाती है। बाद में पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। रोग की उग्र अवस्था में तने और फलों का रंग पीला पड़ जाता है। पौध और फल छोटे रह जाते हैं। यह रोग सफेद मक्खी के द्वारा फैलता है।

प्रबंधन:- रोग नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 एसएल 1 मिली प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। कीटनाशी छिड़काव से पहले तैयार फलो को तोड लें। कीटनाशी छिड़काव के बाद एक सप्ताह तक फलों का प्रयोग नहीं करें।

खरीफ प्याज के लिए तैयार करें नर्सरी

प्रदेश में प्याज की खेती वृहद् पैमाने पर की जाती है। यही कारण है कि दूसरे राज्यों के व्यापारी राजस्थान आकर प्याज की बड़ी मात्रा में खरीद करते है। हालांकि, इस वर्ष प्याज उत्पादकों को बेहत्तर भाव के अभाव में फसल से नुकसान उठाना पड़ रहा है। हालात यह है कि थोक में प्याज 4-5 रुपए प्रति किग्रा की दर से बिक्री हो रहा है। लेकिन, खरीफ में प्याज के दाम अक्सर बढ़ते है। ऐसे में किसान खरीफ प्याज की खेती वैज्ञानिक तरीके से करके अच्छी उपज ले सकता हैं । खरीफ प्याज बुवाई करने वाले किसान इस समय नर्सरी तैयार कर सकते है।

भूमि का चयन- बलुई दोमट, दोमट
तैयारी- खेत की गहरी जुताई, रोपाई के लिए दो-तीन बार कल्टीवेटर चलाकर मिट्टी को भुर-भुरा बना ले।
किस्म- एग्री फाऊंड डार्क रेड, एन-53, अर्का कल्याण, अर्का प्रगति
पौध तैयार करने का समय- मई से जून मध्य तक।
बीज दर- 6-8 किग्रा प्रति हैक्टयर
पौध रोपाई- 7-8 सप्ताह बाद
बीजोपचार- थायरम 2.5 ग्राम प्रति किग्रा बीज।

नर्सरी तैयार करना

एक हैक्टयर में प्याज की खेती हेतु 7.5 मीटर लंबे, एक मीटर चौड़े, जमीन से 15 सेमी. ऊंची बनाई गई 25 नर्सरी बेड़ पर्याप्त होती है। तैयार नर्सरी बेड़ में 40-50 किग्रा. सड़ा हुआ गोबर खाद और 500 ग्राम 15:15:15 अनुपात वाला एनपीके खाद मिलाना चाहिए। प्याज के बीजों को 5-7 सेमी. दूरी पर नर्सरी बेड़ पर कतार में बोना चाहिए। 10-15 दिनों के अंतराल में 2 मिली कैप्टान अथवा 2 मिली कॉपर आक्सीक्लोराईड प्रति लीटर के घोल से नर्सरी बेड़ पर छिड़काव करना चाहिए। बीज बुवाई के बाद बेड़ को घास से ढक देना चाहिए। नर्सरी में नमी बनाए रखे।

डॉ. अवधेश मिश्रा, एनएचआरडीएफ, कोटा

अनार के नये बगीचों की स्थापना

अनार अर्द्धशुष्क जलवायु के लिए महत्वपूर्ण फसल हैं। पिछले कुछ सालों से प्रदेश के पश्चिमी जिलों में अनार बागवानी की तरफ किसानों का रूझान बढ़ा हैं। इसके परिणाम स्वरूप अनार फसल के सकल क्षेत्र में भी वृद्धि देखने को मिली हैं। अनार एक संवेदनशील फसल हैं। वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग किए बगैर अनार की फसल से मुनाफा लेना संभव नहीं हैं। अनार बगीचा स्थापना से जुड़ी वैज्ञानिक जानकारी आलेख में दी गई हैं।

नए बगीचे की स्थापना

मृदा- हल्की दोमट
कतार की दूरी- 4 मीटर
पौधे से पौधे की दूरी- 3 मीटर

गड्ढ़े का आकार- 50 गुना 50 गुना 50 सेमी (लम्बाई-चौड़ाई-गहराई)। गड्ढ़े पौध लगाने के एक माह पूर्व तैयार करें।

गड्ढे को भरना- रोपाई से एक दिन पूर्व गड्ढे के नीचे और साइड की दीवार पर 4.0 मिली. की दर से क्लोरपायरीफॉस 20 ईसी 4-5 लीटर घोल का छिड़काव करें। 100 ग्राम प्रति गड्ढे के हिसाब से 0.33 प्रतिशत क्लोरीन पाउडर (ब्लीचिंग पाउडर) का भुरकाव करें। गड्ढे को बालू मिट्टी, दोमट मिट्टी और चिकनी मिट्टी के बराबर अनुपात में भरें। अनार के पौधे को लगाने से पूर्व नर्सरी में पौधे पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2.5 ग्राम प्रति लीटर और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 0.25 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करें। अनार के बगीचे में वायुरोधी वृक्ष के रूप में सरू (कजूरिना), ग्रेविलिया रोबस्टा (सिल्वर ओक), सेसेबेनिया ग्रान्डीफ्लोरा लगावें।

उर्वरक

गोबर की खाद- 10 किग्रा.
वर्मी कम्पोस्ट- 1.0 किग्रा.
नीम केक- 0.5 किग्रा.
ट्राइकोड्रर्मा पाउडर- 25 ग्राम
फास्फेट सोल्यूब्लाइजिंग बैक्टीरिया (पी.एस.बी.)-25 ग्राम
स्यूडोमोनास फ्लोरेन्स- 25 ग्राम
एजोटोबेक्टर फोरमुलेशन- 25 ग्राम
एजोस्पीरिलम फोरमुलेशन- 25 ग्राम
उन्नत किस्म : सिंदूरी, ढोलका, गणेश, जोधपुर रेड (जोधपुर लाल) जालोर सीडलेस, मृदुला, जी 137 आदि।

स्वीटकॉर्न में कीट-रोग नियंत्रण

स्वीट कॉर्न कम समय में तैयार होने वाली फसल है। इसकी खेती से किसान वर्षभर आमदनी प्राप्त कर सकते है। इस फसल को अनेक कीट-रोग नुकसान पहुंचाते है। स्वीटकॉर्न का राजस्थान में क्षेत्रफल अधिक नहीं है। लेकिन, मेवाड़ और जयपुर क्षेत्र के किसान स्वीटकॉर्न का उत्पादन ले रहे है। आलेख में स्वीटकॉर्न में कीट-रोग प्रबंधन पर जानकारी दी गई है।

स्वीट कॉर्न कम समय में तैयार होने वाली फसल है। इसकी खेती से किसान वर्षभर आमदनी प्राप्त कर सकते है। इस फसल को अनेक कीट-रोग नुकसान पहुंचाते है। स्वीटकॉर्न का राजस्थान में क्षेत्रफल अधिक नहीं है। लेकिन, मेवाड़ और जयपुर क्षेत्र के किसान स्वीटकॉर्न का उत्पादन ले रहे है। आलेख में स्वीटकॉर्न में कीट-रोग प्रबंधन पर जानकारी दी गई है।

कीट

तना छेदक : फसल 15 दिन के होने की अवस्था पर कार्बोफ्यूरान 3 प्रतिशत कण 5-8 किग्रा प्रति हैक्टयर की दर से पौधों के पोटो में डालें।

मोयला : पौधों में नर मंजरी निकलते समय इसका आक्रमण होता है। नियंत्रण हेतु 250 से 300 मिली फॉस्फोमिडॉन 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर बनाकर छिड़काव करें।

रोग

कर्वुलेरिया पत्ता धब्बा : मैन्कोजेब 0.2 मिली प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें।

कृषि सलाह

किसान भाईयों कृषि कार्यों को समय पर करने से और उन्नत कृषि विधियां अपनाने से कृषि से अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। समय पर कृषि क्रियाएं करने से रोग व कीटों का आक्रमण कम हो जाता है तथा इनसे होने वाली हानि को रोककर उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। किसानों के लिए कृषि कार्यों में इस सप्ताह 20 मई से 26 मई तक किए जाने वाले कृषि कार्य निम्न हैं।

- कपास की बुवाई इस सप्ताह कर सकते है। बुवाई से पहले खेतों में प्रयाप्त नमी होना आवश्यक है। बीज किसी प्रमाणितस्रोत से ही खरीदें। उपयुक्त किस्में- एम. आर. सी.- 7017, एम. आर. सी.- 7365, एन. सी. एस.- 855, जय, जे.के.सी.एच.- 99, एस.पी.- 7149, के.सी.एच.एच.- 8152 और के.सी.एच.एच.- 932
- भिंडी की फसल में तुड़ाई के बाद यूरिया / 5.10 किग्रा प्रति एकड़ की दर से डाले तथा माईट कीट की निरंतर निगरानी करते रहें। अधिक कीट पाये जाने पर ईथियॉन/1-5.2 मि.ली. प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव आसमान साफ होने पर करें। इस मौसम में भिंडी की फसल में हल्की सिंचाई कम अंतराल पर करें।
- तापमान को ध्यान में रखते हुए सभी सब्जियों तथा खड़ी फसलों में आवश्कतानुसार हल्की सिंचाई करें। सिंचाई सुबह अथवा शाम के समय ही करें।
- ग्रीष्मकाल हरी खाद के लिए सनई, ढैंचा, ग्वार, लोबिया, मूंग आदि की बुवाई कर सकते हैं। सनई की बीज दर 60.70 और ढैंचा की 50.60 किग्रा प्रति हैक्टयर। अच्छे अंकुरण के लिए खेत में पर्याप्त नमी होनी आवश्यक है।
- ग्वार, मक्का, बाजरा, लोबिया आदि चारा फसलों की बुवाई इस सप्ताह कर सकते हैं। बुवाई के समय खेत में पर्याप्त नमी होनी आवश्यक है। बीजों को 3.4 सेमी गहराई पर डाले और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 25.30 सेमी रखें।
- किसान अरहर और कपास की बुवाई के लिए खेतों को तैयार करें तथा बीज किसी प्रमाणित स्रोत से ही खरीदें।
- बैंगन तथा टमाटर की फसल को प्ररोह और फल छेदक कीट से बचाव हेतु ग्रसित फलों तथा प्ररोहों को इकट्ठा कर नष्ट कर दें। यदि कीट की संख्या अधिक हो तो स्पिनोसेड कीटनाशी 48 ईसी / 1 मिली प्रति 4 लीटर पानी की दर से छिड़काव आसमान साफ होने पर करें।
- इस मौसम में बेलवाली फसलों में न्यूनतम नमी बनाएं रखें अन्यथा मृदा में कम नमी होने से परागण पर असर हो सकता है जिससे फसल उत्पादन में कमी आ सकती है।

नेपियर घास, उत्पादन तकनीक

बहुवर्षीय हरे चारे की खेती में नेपियर घास की खेती एक अच्छा विकल्प हो सकता हैं। इससे दूसरी चारा फसलों की अपेक्षा कई गुणा हरा चारा प्राप्त हो सकता हैं। साथ ही, इसकी खेती से 4-5 वर्षो तक बुवाई पर होने वाले व्यय की भी बचत की जा सकती हैं। नेपियर घास एक बहुवर्षीय चारे की फसल है। यह तीव्र वृद्धि, शीघ्र पुनर्वृद्धि, अत्यधिक कल्ले, अत्यधिक पत्तियों आदि गुणों के साथ-साथ 2000 से 2500 क्विंटल प्रति हैक्टयर प्रति वर्ष हरा चारा देने में सक्षम हैं। यह 40 दिनों में 4 फीट तक उंची हो जाती हैं तथा इस अवस्था पर इसका पूरा तना और पत्तियाँ हरी रहती है। जिसके कारण यह रसीली और सुपाच्य होती हैं और पशु इसे बड़े चाव से खाते हैं। इसके पौधे गन्ने की भांति लम्बाई में बढ़ते हैं जिनसे 40-50 तक कल्ले निकलते हैं। इसे हाथी घास के नाम से भी जाना जाता है। बहुवर्षीय फसल होने के कारण इसकी खेती शरद, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में की जा सकती है।

भूमि- 6.5 से 8 पीएच मान

उन्नत किस्मः- पूसा जायन्ट नेपियर, नेपियर बाजरा हाईब्रिड-21 (एनबी.-21), पूसा नेपियर 1, 2 (सर्दियों में भी उत्पादन सम्भव), एपीबीएन-1, सीओ. 2, 3, 4, पीबीएन-233, एनबी -17, 25, एमबी.-8-95, पीएनबी-87, 72, आईजीएफआरआई-293, 6,7,9 आदि।

खेत की तैयारीः- मिट्टी पलटने वाले हल अथवा डिस्क प्लाऊ से 2-3 जुताई के बाद पाटा लगाकर। अन्तिम जुताई से पूर्व सड़ी हुई गोबर की खाद अथवा कम्पोस्ट को खेत में बिखेर कर मिला देना चाहिए।

बीज दर

पौधे से पौधे की दूरी	लाईन से लाईन की दूरी	टुकड़े	वजन
30 से.मी.	2 मी. (200 से.मी.)	16500 से 17000	12-13 क्विंटल
30 से.मी.	1 मी. (100 से.मी.)	32000 से 33000	24-25 क्विंटल
30 से.मी.	90 से.मी.	40000	30-32 क्विंटल
30 से.मी.	75 से.मी.	45000	35-36 क्विंटल

खाद- 15-20 टन गोबर खाद।

उर्वरक- 50-60 किलो नाइट्रोजन, 80-100 किलो फॉस्फोरस और 25-30 किलो पोटाश प्रति हैक्टयर।

असिंचित क्षेत्र में- जुलाई-अगस्त

रोपाई विधि

बुवाई हमेशा लाईनों में मेड़ों पर करनी चाहिए। उपर्युक्त दूरी पर लाइन बनाकर 2-3 गांठ वाले टुकड़ों को भूमि में 45 डिग्री के कोण पर इस प्रकार लगाए कि टुकड़े की एक गांठ जमीन के अन्दर और दूसरी जमीन

से ऊपर रहे। टुकड़ों का झुकाव ठीक उसी प्रकार करे जैसे गन्ने की बुवाई की जाती है। बुवाई के तुरन्त बाद सिंचाई अवश्य करनी चाहिए।

डॉ. योगेश कनोजिया, रमेश कुमार डामोर, कृषि विज्ञान केन्द्र, प्रतापगढ़

खजूर का दैनिक जीवन में उपयोग

खजूर मीठे फलों का राजा है। खजूर फल छोट-छोटे होते हैं और इनके बीज सख्त और दोनों सिरों से गोल होते हैं। खजूर के पेड़ को आल पर्पस ट्री के नाम से भी जाना जाता है। मुस्लिम समुदाय में खजूर को बहुत अधिक मान्यता प्राप्त है। रमजान के दिनों में अपने रोजे को खोलने के लिए खजूर का ही प्रयोग किया जाता है। खजूर के पेड़ से रस निकालकर नीरा बनाई जाती है। जो तुरन्त पीने पर बहुत पौष्टिक होती है और कुछ समय तक रखी जाए तो शराब बन जाती है। इसके रस से गुड़ भी बनाया जाता है।

खजूर खाने के लाभ

पेट के कीड़ : किसी के पेट में कीड़े है, तो सुबह सुबह खाली पेट खजूर का सेवन करें। इससे उसके पेट में जो भी कीटाणु है वह खत्म हो जायेंगे।

दुर्बलता : एक गिलास दूध में 4 छुहारे उबालकर ठण्डा कर लें और पिएं। सर्दी में इसका सेवन करना चाहिए।

त्वचा : खजूर त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद है। इसके नियमित सेवन से त्वचा चमकदार बनती है।

रक्त पूर्ति : अगर आपके शरीर में रक्त की कमी है तो प्रतिदिन खजूर खाने से आपके शरीर में रक्त की कमी को पूरा किया जा सकता है।

घाव : छुहारे की गुठली को पानी के साथ पत्थर पर घिसकर, इसका लेप घाव पर लगाने से घाव ठीक होता है।

ब्लड प्रेशर : ब्लड प्रेशर रोगी प्रतिदिन 3 से 4 खजूर को दूध में डालकर सेवन करें तो इससे ब्लड प्रेशर नियंत्रण में रहता है।

कब्ज : खजूर, कब्ज को दूर भगाने की शक्ति रखता है। 3 से 4 खजूर को खाने के बाद आप गुनगुना पानी पी लें। आपको कब्ज से राहत मिलेगी।

शरीर में स्फूर्ति : नियमित खजूर खाने से शरीर को स्फूर्ति प्राप्त होती है। 3 से 4 खजूर रात में पानी में भिगों दे। सुबह सुबह उसका सेवन करें तो इससे आपको लाभ मिलेगा।

मूत्र रोग : अगर आपको मूत्र सम्बन्धी रोग है तो 2 खजूर को सुबह दूध के साथ सेवन करने से लाभ मिलेगा।

जयदेव हालदार, एमजीसीजीवि, चित्रकूट, सतना (मप्र)

चने की नई किस्म आरवीजी-204

नवीन अनुसंधान

ग्वालियर। राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध रफी अहमद किदवई कृषि महाविद्यालय, सिहोर के कृषि वैज्ञानिकों ने देशी चने की नई किस्म राज्य विजय ग्राम (आरवीजी-204) तैयार की है। नई किस्म की खासियत यह है कि इस फसल की लंबाई ढाई से तीन फीट होगी। साथ ही, फली ऊपरी हिस्से में लगेगी। इस कारण मशीन से फसल की कटाई करना आसान होगा। वर्तमान देशी चने की फसल जो किसान उगाते हैं उसकी लंबाई डेढ़ से दो फीट रहती है। साथ ही, फल नीचे के हिस्से से लगना शुरू होते हैं। इससे किसान मशीन से फसल की कटाई नहीं कर पाते। कृषि महाविद्यालय के प्रभारी डॉ. डीआर सक्सेना के मुताबिक चने की नई किस्म मशीन से कटाई के लिए उपयुक्त है।

यह है खासियत

पकाव अवधि- 120 दिन

दाना- हरे रंग का (पकाव बाद)

उपयोग- सब्जी और प्रसंस्कृत उत्पाद के लिए

उत्पादन-15-20 क्विंटल प्रति हैक्टयर

सम्पर्क सूत्र - 09893197642

पॉली हाउस में सूत्रकृमि नियंत्रण

पॉली हाऊस में उगाई गई फसल की अच्छी गुणवत्ता के चलते किसान को ज्यादा भाव मिलते है। लेकिन, पॉली हाउस में जड़गांठ सूत्रकृमि की बढ़ती समस्या से किसानों को नुकसान होने लगा है। पॉलीहाउस में अनुकूल वातावरण पाकर सूत्रकृमि तेजी से अपनी वृद्धि करते है। जो खीरा, टमाटर, मिर्च और पुष्प फसल को अपना शिकार ज्यादा बनाते है। गांठ बनने के कारण सूत्रकृमि द्वारा लगने वाले रोग को पौधों का कैंसर भी कहा जाता हैं।

ऐसे करें प्रबंधन

सूत्रकृमि प्रबन्धन हेतु पॉली हाऊस को स्थापित करने से पूर्व और बाद में बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिसमें से मुख्य निम्न हैं:-

- पॉली हाउस स्थापना से पूर्व मृदा जांच करवाये।
- पॉली हाउस की दीवार जमीन से 1 से दो फीट ऊंची बनाये।
- पॉली हाऊस के मुख्य द्वार पर सीमेंट का एक फीट गहराई का थालेनुमा टांका बनाना चाहिए, जिसमें पानी भरा रहे और पानी की निकासी बाहर की ओर हो। इससे पॉली हाऊस में प्रवेश करने वाला प्रत्येक व्यक्ति वहाँ से गुजरे तब उसके पैर उस पानी में स्वतः धुल जाये। सामान्यतः उस पानी में फिनायल अथवा नीला थोथा मिलाना लाभदायक रहता है।
- पॉली हाऊस में प्रयुक्त सभी यंत्र और औजार का प्रयोग पॉली हाऊस से बाहर नहीं करना चाहिए।
- मृदा रहित निर्जमीकृत माध्यम जैसे कोकोपिट, फॉम ब्लॉक, रॉक वुल आदि का प्रयोग करना चाहिए, जो सूत्रकृमि से संक्रमित नहीं हो।
- पॉली हाऊस के अन्दर ही नर्सरी अथवा प्रो ट्रे / प्लास्टिक ट्रे में तैयार करनी चाहिए।

गर्म जलोपचार

- इसके अन्तर्गत ऐसी फसल जिनका प्रवर्धन शल्ककन्द, कन्द, घनकन्द, भूस्तारी आदि द्वारा किया जाता है उनको उपचारित करते हैं। इसमें पादप भाग को 50 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 20 मिनट तक रखकर सूत्रकृमि से मुक्त किया जा सकता है। साथ ही, पॉली हाऊस में नई फसल लगाने से पूर्व मृदा को गर्म पानी से उपचारित करना चाहिए।

कार्बनिक पदार्थ

- सूत्रकृमि प्रबन्धन हेतु गोबर की खाद, पोल्ट्री खाद अथवा वर्मी कम्पोस्ट 3-4 क्विंटल मात्रा प्रति 1000 वर्गमीटर में प्रयोग करना लाभदायक पाया गया है। कार्बनिक पदार्थ के रूप में तम्बाकू की चूरी, चाय का व्यर्थ पदार्थ, नीम, लेन्टाना और जलकुम्भी की पत्तियों को भी मृदा में मिला सकते हैं, जिससे सूत्रकृमि की संख्या में कमी हो जाती हैं नीम/करंज/महुआ की खली 200-250 किलोग्राम मात्रा प्रति 1000 वर्गमीटर की दर से प्रयोग करे।

जैव कारक

कवकजनित जैवकारक के अन्तर्गत पेसिलोमाइसिस लिलासीनस, ट्राइकोडर्मा विरिडी/हरजियानम, पोचोनिया क्लेमायडोस्पोरिया और जीवाणुजनित के अन्तर्गत स्यूडोमोनास फ्लोरसेन्स और पाश्चुरिया पेनेट्रान्स आते हैं। जैवकारकों का

प्रयोग मुख्यतः दो रूप में किया जाता है:-

बीजोपचारः 10-20 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से

मृदापचारः 2 किग्रा जैवकारक को 100 किग्रा कार्बनिक पदार्थ के साथ मिलाकर 15 दिन तक उचित नमी के साथ रखते हैं जिससे जैवकारक अच्छी वृद्धि कर सके। इसकी 250 ग्राम मात्रा प्रति वर्गमीटर की दर से प्रयोग करते हैं।

रासायनिक उपचारः- सूत्रकृमि रोग की अधिकता वाली अवस्था में सूत्रकृमियों का नियंत्रण करने हेतु कई रसायनों का अलग-अलग रूप (धूमण, बीजोपचार और मृदापचार) में प्रयोग किया जा सकता है, जो निम्नलिखित हैं:-

धूमणः धूमण हेतु मुख्यतः फॉर्मलीन 250 मिली. प्रति मेथाम सोडियम 30 मिली. अथवा सोडियम टेट्राथायो कार्बामेट 30 मिली का प्रयोग किया जा सकता है। धूमण के दौरान मृदा को पॉलीथीन शीट से ढ़कना चाहिए।

धुमण में सावधानी

- मुंह पर कपड़ा अथवा मास्क बांधे।
- धूमण के तुरन्त पश्चात् पॉली हाऊस से प्रयोगकर्ता को बाहर निकल जाना चाहिए। एक सप्ताह तक किसी का प्रवेश पॉलीहाउस में नहीं हो।
- धूमण के समय पॉलीथिन शीट को चारों ओर से मिट्टी में दबा देना चाहिए। ताकि, अन्दर की विषाक्त गैस बाहर नहीं निकल सके।
- रसायन की मात्रा वैज्ञानिक सिफारिशानुसार ही उपयोग करें।

बीजोपचारः कार्बोसल्फॉन 25 डी एस 3 ग्राम/किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करे।

मृदापचारः रोग की अधिकता होने पर कार्बोफ्यूरान 3 जी की 2 किलोग्राम सक्रिय तत्व मात्रा प्रति हैक्टयर की दर से उपयोग करे।

फसली बीजों का भंड़ारण

भण्डारण के दौरान अनाज की गुणवत्ता और मात्रा दोनों में कमी आती है। इस गुणवत्ता को फसल कटाई के बाद बीज को कम नमी और कम तापमान पर रखने से काफी समय तक रोका जा सकता है । लेकिन, बीज भण्डारण के स्थान पर जहां अधिक नमी हो तो बीज में अनेक प्रकार के कीट और कवक का बीज पर आक्रमण हो जाता है। इससे बीज की गुणवत्ता को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। प्रसंस्कृत बीज के लिए परिवहन और भंड़ारण का तरीका वैज्ञानिक होना चाहिए। क्योंकि, इसका प्रभाव बीज अंकुरण क्षमता पर पड़ता है। इसके कारण लगभग 10 प्रतिशत अनाज बर्बाद हो जाता हैं। जिसे अनाज भडारण की उचित विधियाँ अपना कर बर्बाद होने से बचाया जा सकता हैं।

भण्डार गृह के लिए महत्वपूर्ण बिन्दुः-

स्थान का चुनाव : भंड़ारण का स्थान ऊंचा हो। भंड़ार गृह में दीमक का प्रकोप नहीं हो। पानी और वर्षा जल की पहुंच से दूर हो। भंड़ार गृह की खिड़कियाँ बंद हो। भण्डार गृह छाया वाले स्थान पर हो।

भण्डार गृह की सफाई : भण्डार गृह में खाली स्थान (बोरियों के अलावा) की सप्ताह में एक बार और बोरियों की एक माह के अन्तराल पर सफाई करनी चाहिए।

गेहूं-जौ : डेल्टामेथ्रिन 4 मिली को आधा लीटर पानी में मिलाकर प्रति 100 किलोग्राम बीज की दर से सीड ड्रेसर में मिलाकर बीज को अच्छी तरह सुखाकर बोरियों में भरकर एक साल तक कीट रहित भंडारण किया जा सकता है।

नीम और पलास तेल 5 मिली प्रति किग्रा बीज की दर से उपयोग करके गेहूं के बीज को एक वर्ष तक घुन से सुरक्षित किया जा सकता है ।

दलहन बीज : थायरम 2.5 ग्राम प्रति किलो का उपयोग कर बीज को धौरा कीट से सुरक्षित रखा जा सकता है।

चने के बीज को मूंगफली अथवा सरसों के तेल से 10 मिली प्रति किलो की दर से उपचारित करके धौरा कीट के प्रकोप से सुरक्षित रखा जा सकता है ।

बोरियों पर डेल्टामेथ्रिन 2.5 डब्लूपी अथवा 125 पीपीएम से अच्छी तरह छिडकाव कर सुखा लेना चाहिए। फिर इनमें बीज भरकर रखने से 6 महीनें तक कीट से सुरक्षित रखा जा सकता है।

मूंग के बीज को थायोमिथाक्सम 70 डब्लूएस 2.8 मिग्रा अथवा डेल्टामेथ्रिन 2.5 डब्लपी 40 मिग्रा प्रति किग्रा की दर से उपचारित करके जूट की बोरियों में 9 महीनें तक सुरक्षित रखा जा सकता है।

कपास बीजः बीजों को धूमित करने हेतु 40 किलो बीज में एल्युमीनियम फास्फाईड की 3 ग्राम मात्रा मिलाकर उसे हवा रोधी बनाकर 24 घंटे तक बन्द रखने के बाद भण्डारण करे अथवा तेज धूप में बीज को फैला कर 6 घंटे तक तपन देवें।

सब्जी बीज : मिर्च, प्याज बीज के सुरक्षित भण्डारण के लिए 700 गेज पोलिथीन का प्रयोग करें। बैग में भरने से पूर्व बीज पूरी तरह सूखा होना चाहिए (नमी 5 प्रतिशत अथवा 5 से कम) बीजों को कीट रहित करने के लिए फ्यूमिगेशन पद्धति का प्रयोग करें।

फसल सुरक्षा के लिए जैविक कीटनाशक निर्माण

फसल सुरक्षा का एकमात्र उपाय जैविक और प्राकृतिक खेती है। इसलिए प्रदेश सरकार भी किसानों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। गौरतलब है कि रासायनिक कीटनाशक के छिड़काव से खेत में मौजूद मित्र कीट और जीव नष्ट हो रहे है। वहीं, नई-नई बीमारियां मानव स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है। जैविक खेती में प्रयोग किये जाने वाले कुछ जैव कीटनाशक तैयार करने की जानकारी आलेख में दी जा रही है। जो प्रदेश सरकार के जैविक मिशन को आगे बढ़ाने में उपयोगी साबित होगी।

बीजामृत

देसी गाय का गोबर- 5 किग्रा, देसी गाय का गौमूत्र-5 लीटर, खेत के मेड़ की मिट्टी-200 ग्राम, चूना-50 ग्राम, पानी 20 लीटर।

बनाने की विधिः उपरोक्त सभी सामग्री को 20 लीटर पानी में मिलाकर मिट्टी के मटके में 2 दिन तक रखें। इस घोल को दिन में दो बार लकड़ी से घोलें। तत्पश्चात् साफ सूती कपड़े से छानकर बुवाई के दिन बीजों का उपचार करें।

उपयोग : इसमें 100 किलोग्राम बीजों का उपचार करके छांव मे सुखाकर बुवाई करें। यह बीजों को रोग रहित बनाने और उनकी अंकुरण क्षमता बढ़ाने में उपयोगी हैं।

जीवामृत (1 एकड़ खेत के लिए)

देसी गाय का गोबर- 30 किग्रा, देसी गाय का गौमूत्र-10 लीटर, दीमक मिट्टी-100 ग्राम, गुड-2 किग्रा, पानी 200 लीटर, बेसन 2 किग्रा।

बनाने की विधिः उपरोक्त सामग्री को एक टॉका अथवा ड्रम में मिलाकर 5- 6 दिन के लिए छायादार स्थान में रख देते हैं। इस घोल को दिन में दो बार हिला देते हैं। इस तरह जीवामृत तैयार हो जाएगा।

जीवामृत का प्रयोग

- जीवामृत का प्रयोग हर सिचांई के साथ करें।
- सब्जी फसल में पौधे से आधा फीट की दूरी पर 250 मिली लीटर डालना हैं।
- जीवामृत को धान की फसल में सिचांई के साथ 3 से 4 बार दिया जा सकता हैं।

अमृत पानी

देसी गाय का गोबर- 5 किग्रा, देसी गाय का गौमूत्र-5 लीटर, गुड-5 ग्राम, पानी 5 लीटर, बेसन 500 किग्रा और नीम पत्ती।

बनाने की विधिः उपरोक्त सभी सामग्री को मिलाकर मिट्टी के बर्तन में 5 से 6 दिन के लिए रख देते है, दिन में दो बार लकड़ी की सहायता से हिलाते है।

अमृत पानी का प्रयोग

तैयार अमृत पानी को सूती कपड़े से छानकर 50 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर फसल में विटामिन के रूप में स्प्रे कर सकते हैं। यह जीवाणुनाशक और पौधे में वृद्धि हार्मोन के रूप में कार्य करता है। किसी भी फसल में यह 10 से 15 दिन के अन्तराल में 6 से 8 बार स्प्रे किया जा सकता है।

नीमास्त्र (नीम गौ-मूत्र सत)

नीमास्त्र का उपयोग रसचूसक, छोटी सुंडी, इल्ली , फल छेदक, तना छेदक आदि कीट नियंत्रण की रोकथाम के लिए किया जाता है।

नीम पत्ती युक्त टहनी-5 किग्रा, नीम फल-5 किग्रा, गौमूत्र-5 लीटर, गाय का गोबर-1 किग्रा।

5 किलोग्राम नीम पत्तियां युक्त टहनियां

बनाने की विधि : सर्वप्रथम प्लास्टिक के बर्तन में 5 किलोग्राम नीम की पत्तियों को बारिक काटकर, कूटकर और 5 किलोग्राम नीम के फल (पीस - कूटकर) में डालें । 5 लीटर गोमूत्र और 1 किलोग्राम गाय का गोबर डाले। इन सभी सामग्री को डंडे से मिक्स करके जालीदार कपड़े से ढक दें। यह 48 घण्टे में तैयार हो जाएगा। 48 घण्टे (2 दिन) में चार बार डंडे से चलाए।

भण्डारण : नीमास्त्र का प्रयोग छः माह तक कर सकते हैं। नीमास्त्र को मिट्टी अथवा प्लास्टिक के बर्तन में भरकर छाया में रखें और धूप से बचाएं। गौमूत्र प्लास्टिक के बर्तन में रखें।

ब्रह्मास्त्र : ब्रहास्त्र का उपयोग सभी प्रकार के रस चूसक, फल छेदक , तना छेदक, कीट और बड़ी सुंडी, इल्ली आदि नियंत्रण के लिए किया जाता हैं।

सामग्रीः- गौमूत्र-10 लीटर, नीम की पत्ती-3 किग्रा, करंज पत्ती-2 किग्रा, सीताफल पत्ती-2 किग्रा, बेल की पत्ती-2 किग्रा, धतूरा पत्ती-2 किग्रा, अरंडी पत्ती-2 किग्रा, आक की पत्ती-2 किग्रा।

बनाने की विधिः मिट्टी के बर्तन में गौमूत्र डालकर सभी सामग्री की चटनी बनाकर 1 दिन के लिए छायादार स्थान पर रख देते है। अब बर्तन आग पर चढ़ाकर मिश्रण को उबालें। जब चार उबाल आ जाए तो आग से उतारकर 48 घण्टे छाया में ठंडा होने दें। इसके बाद कपड़े से छानकर प्रयोग करें।

भण्डारण : ब्रहमास्त्र का प्रयोग छः माह तक कर सकते हैं। भण्डारण मिट्टी के बर्तन में करें। ब्रहमास्त्र को छाया में रखें। गौमूत्र प्लास्टिक के बर्तन में रखें।

छिड़कावः प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में तैयार 10 लीटर ब्रहमास्त्र को छानकर मिलाए। स्प्रे मशीन से छिड़काव करें।

आग्नेयास्त्र

आग्नेयास्त्र का उपयोग तना छेदक, फल छेदक, रस चूसक कीट और फल सुंडी- इल्ली नियंत्रण के लिए किया जाता हैं।

सामग्रीः- गौमूत्र-20 लीटर, तम्बाकू पाउडर-500 ग्राम, हरी तीखी मिर्च-500 ग्राम, लहसुन चटनी-500 ग्राम, नीम पत्ती-5 किग्रा।

बनाने की विधिः सामग्री को एक मिट्टी के बर्तन में डालें और गर्म करें। चार बार उबाल आ जाने के बाद आग से उतारकर ठंडा करें। आग से उतारने के बाद 48 घण्टे छाया में रखें। चार बार डंडे से चलाए।

भण्डारणः आग्नेयास्त्र का भण्डारण केवल तीन माह तक कर सकते हैं। उबालने के लिए मिट्टी के बर्तन को ही लें, गौमूत्र के बर्तन में नहीं लें । ना ही भण्डारित करें।

छिड़काव : प्रति एकड़ के लिए 5 लीटर अग्नि अस्त्र का साफसूती वस्त्र से छानकर 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे मशीन और नीम की डालियों से छिड़काव करें।

दशपर्णी अर्क

दशपर्णी अर्क का प्रयोग सभी तरह के रस सूचक कीट और सभी इल्ली के नियत्रंण के लिए किया जाता हैं।

सामग्रीः पानी-200 लीटर, गौमूत्र-10 लीटर, धतूरा पत्ते-2 किग्रा, सीताफल पत्ते-2 किग्रा, पपीता पत्ते-2 किग्रा, नीम पत्ते-5 किग्रा, आक पत्ते-2 किग्रा, बेल के पत्ते-2 किग्रा, पीसा हुआ तम्बाकू-500 ग्राम, लहसुन-500 ग्राम, तीखी हरी मिर्च-500 ग्राम, गाय का गोबर-2 किग्रा, करंज के पत्ते-2 किग्रा, तुलसी पत्ते-2 किग्रा, गेंदे के पत्ते-2 किग्रा, कनेर के पत्ते-2 किग्रा, पीसी हल्दी-500 ग्राम, अदरक-200 ग्राम।

बनाने की विधि : प्लास्टिक के ड्रम में 200 लीटर पानी डालें। इसमें 2 किग्रा गाय का गोबर और 10 लीटर गौमूत्र मिला दें। अब इसमें नीम, करंज, सीताफल, धतुरा, बेल, तुलसी, आक, पपीता, कनेर, गेंदा के पत्ती की चटनी (कोई दस) डालें और डंडे से चलाए। दूसरे दिन तम्बाकू , मिर्च, लहसुन, सोंठ, हल्दी डालें। डंडे से चलाकर जालीदार कपड़े से बंद कर दें। 40 दिन छाया में रखा रहने दें, परन्तु प्रतिदिन सुबह शाम डंडे से हिलाते जरूर रहें।

भण्डारण : इसको छः माह तक प्रयोग कर सकते हैं। इस दशपर्णी अर्क को छाया में रखें। बनाते समय इसको सुबह-शाम हिलाना नहीं भूलें।

छिड़कावः प्रति एकड़ के लिए 200 लीटर पानी में 10 लीटर दशपर्णी अर्क मिलाकर छिड़काव करें।

फंगस नियंत्रण : 100 लीटर पानी में 3 लीटर खट्टी छाछ (मट्ठा) को खूब अच्छी तरह मिलाकर फसल में छिड़काव करें।

6 जून को केरल में देगा दस्तक

पांच दिन देरी से आयेगा मानसून

नई दिल्ली। स्काईमेट के बाद अब मौसम विभाग ने कहा है कि इस बार मानसून के देरी से आने की संभावना है। यह छह जून को केरल में दस्तक देगा। हालांकि, इसमें पांच दिन की देरी और हो सकती है। गौरतलब है कि हर साल 1 जून को मानसून केरल में दस्तक देता है। लेकिन , अब मौसम विभाग के अनुसार इसकी शुरुआत में ही पांच दिन की देरी हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिणपूर्व मानसून इस बार अंडमान-निकोबार भी थोड़ा देरी से पहुंचेगा। इसके यहां 18-19 मई तक पहुंचने की संभावना है। ऐसा इसलिए क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में मानसूनी हवाएं देर से उठेंगी।

अर्थव्यवस्था से जुड़े हैं मानसून के तार

मानसून का सीधा तार देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। किसानों से लेकर के सरकार के बजट पर मानसून अपना प्रभाव दिखाता है। अगर मानसून कमजोर रहता है तो फिर खाद्य उत्पादन कम होगा, जिससे किसानों की दशा और खराब होगी। वहीं इससे महंगाई भी बढ़ेगी, जिसका असर आम लोगों पर पड़ेगा। अनाज, फल-सब्जियों और दूसरी खाने-पीने की चीजों का उत्पादन कम होने से बाजार में इनकी कमी हो जाएगी, जिससे कीमतों पर भी असर पड़ेगा।

सूखे की संभावना ज्यादा

स्काईमेट ने मध्य भारत में सबसे कम 91 प्रतिशत बारिश का अनुमान लगाया है। पूर्वोत्तर में 92प्रतिशत, दक्षिण में 95प्रतिशत और पश्चिमोत्तर में 96प्रतिशत बारिश हो सकती है। इस तरह देश के कई राज्य जैसे कि मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ में सूखा पड़ सकता है।

14 साल में 13 बार सही निकली

भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि पिछले 14 सालों के दौरान मानसून के पहुंचने की उसकी भविष्यवाणी 13 बार सही निकली है, सिर्फ एक बार यानि 2015 में उसका अनुमान सही नहीं गया था। 2015 में मौसम विभाग ने 30 मई को मानसून के केरल तट पर पहुंचने का अनुमान जारी किया था । जबकि , मानसून 5 जून को पहुंचा था।

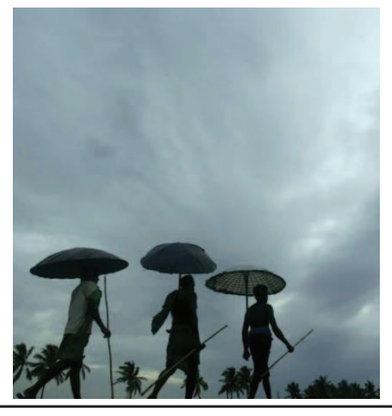

93% बारिश होने का अनुमान

स्काईमेट ने 2019 में 93 प्रतिशत बारिश की संभावना जताई है। मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार इस साल भारतीय उप महाद्वीप में मानसून शुरुआती दौर में थोड़ा कमजोर रहेगा। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत तथा मध्य भारत में कम बारिश की आशंका है। जबकि उत्तर पश्चिम और दक्षिण भारत में स्थिति बेहतर होगी।

अलनीनो का असर

समुद्री हवाओं का रुख बदल जाता है। बारिश वाले क्षेत्रों में बारिश नहीं होती, इसके उलट जिन इलाकों में बारिश नहीं होती है, वहां मूसलाधार बारिश होती है।

सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान 32%

मौसम विभाग के मुताबिक सामान्य से थोड़ी कम यानि 90-96 फीसदी बारिश की संभावना 32 फीसदी और 90 फीसदी से कम बारिश की संभावना 16 फीसदी है। मानसून सीजन के दौरान अगर 90 फीसदी से कम बारिश हो तो सूखाग्रस्त घोषित किया जाता है। यानि इस साल 16 फीसदी संभावना सूखाग्रस्त मानसून की भी है। खरीफ की फसलों की बुवाई के लिए मानसूनी बारिश काफी महत्वपूर्ण है। पिछले खरीफ सीजन में देश के कई राज्यों महाराष्ट्र गुजरात, कर्नाटक और ओडिशा आदि में सामान्य से कम बारिश हुई थी, जिससे इन राज्यों के कई जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया हुआ है।

मोनसेंटो पर 14 हजार करोड़ का जुर्माना

सैन फ्रांसिस्को। अमेरिका की कीटनाशक और कृषि रसायन बनाने वाली कंपनी मोनसेंटो अपने खरपतवार-नाशक प्रॉडक्ट राउंडअप से कैंसर होने से जुड़ी तीसरी कानूनी लड़ाई हार गई है। कैलिफोर्निया स्टेट कोर्ट ने मोनसेंटो को दंपती अल्वा और अलबर्ट पिलोड को 14 हजार करोड़ रु. से ज्यादा का हर्जाना देने का निर्देश दिया है। इस मामले में यह अब तक का सबसे अधिक हर्जाना है। शिकायतकर्ताओं के वकीलों ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया है। अमेरिका में राउंडअप से कैंसर होने की शिकायतों को लेकर लोगों ने विभिन्न अदालतों में 13,000 से ज्यादा मुकदमे दायर किए हैं। उधर, मोनसेंटो पर मालिकाना हक रखने वाली जर्मन कंपनी बायर ने कहा है वह फैसले के खिलाफ अपील करेगी।

नाबार्ड ने बनाया 700 करोड़ का उद्यम कोष

मुंबई। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने कृषि-ग्रामीण क्षेत्र की स्टार्टअप कंपनियों में इक्विटी निवेश के लिए 700 करोड़ रुपये के उद्यम पूंजी कोष की घोषणा की। नाबार्ड अभी तक दूसरे कोषों में योगदान करता है। यह पहली बार है कि जब उसने अपना कोष पेश किया है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि नाबार्ड की अनुषंगी कंपनी नैबवेंचर्स ने यह कोष पेश किया है। इसके लिए 500 करोड़ रुपये की पूंजी का प्रस्ताव किया गया है। साथ ही ओवर-सब्सक्रिप्शन के लिए 200 करोड़ रुपये की अतिरिक्त पूंजी का भी विकल्प है। यह कोष कृषि, खाद्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में काम करने वाली स्टार्टअप कंपनियों में निवेश करेगा। नाबार्ड के चेयरमैन हर्ष कुमार भनवाला ने कहा कि इस कोष से भारत में कृषि, खाद्य और ग्रामीण आजीविका जैसे क्षेत्रों में निवेश तंत्र को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। बयान में कहा गया है कि नाबार्ड ने अब तक 16 वैकल्पिक निवेश कोष में 273 करोड़ रुपये का योगदान किया है।

प्रो. अजय को डेयरी महाविद्यालय का प्रभार

उदयपुर (कास)। सी टी ए ई के अधिष्ठाता प्रो. अजय कुमार शर्मा को डेयरी-खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय के अधिष्ठाता का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। प्रो शर्मा ने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। आपको बता दें कि प्रो. केएल मुरडिया के सेवानिवृत्ति उपरांत प्रो. अजय को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है।

डॉ. सुमन इंडिया बुक ऑफ रिकार्ड में

उदयपुर। महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी छात्र कल्याण निदेशक डॉ. सुमन सिंह का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकार्ड में वुमन रिसर्चर एम्पावरिंग वुमन फार्म्स की श्रेणी में दर्ज हुआ है। डॉ. सुमन को इससे पहले 2009 में बीजिंग में हुई इंटरनेशनल इर्गोनॉमिक्स एसेसिएशन की ट्राइएनियल कांग्रेस में श्रेष्ठ कार्य और शोध के लिए लिबर्टी मैडल से सम्मानित किया जा चुका है।

कृषि विज्ञान केन्द्र भीलवाड़ा का प्रयास

जनजातीय गांवों में बही विकास की गंगा

भीलवाड़ा (कास)। कृषि विज्ञान केन्द्र के कृषि वैज्ञानिकों के भागीरथी प्रयासों के चलते जनजातिय बहुल गांव रावतखेड़ा और रामगढ़ के किसान उन्नत कृषि तकनीक अपनाकर, नए फसली बीज का उपयोग करके और पशुपालन के साथ मुर्गीपालन करके अपनी तकदीर संवारने में जुटे है। आपको बता दें कि प्राथमिक सर्वे के बाद केवीके के द्वारा जनजातीय योजनान्तर्गत वर्ष 2018-19 में गोद लिया गया था। इसके बाद केन्द्र के वैज्ञानिकों ने जनजातिय किसानों को कम लागत वाली आधुनिक कृषि तकनीक से जोड़ना शुरू किया। साथ ही, किसानों को जागरूक बनाने के लिए संस्थागत-असंस्थागत प्रशिक्षण, रात्रि गोष्ठी, प्रदर्शन,पशु चिकित्सा स्वास्थ्य शिविर, किसान मेला, उपचारात्मक भ्रमण, मोबाईल सलाह और वाट्सअप संदेश, दक्षता आधारित रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए गए। इससे चयनित परिवारों की आजीविका में सुधार देखने को मिला है।

ऐसे आया बदलाव

केन्द्र के द्वारा करके सीखना, देखकर विश्वास करना और अपहुंच से पहुंच तक के आधार पर किसानों के द्वार तक तकनीक पहुंचाई गई। इसके तहत केन्द्र द्वारा पिछले साल खरीफ में तिल किस्म आरटी-351, रबी में गेहूं किस्म राज-4079, जौ किस्म आरडी-2786, और चना किस्म जीएनजी-1581 के प्रदर्शन चयनित गाँवों में लगाएं गए। ताकि, किसान की उपज और आय बढे। कृषक परिवारों के पोषण स्तर में सुधार और आजीविका बढ़ाने हेतु 1792 उन्नत प्रजाति (प्रतापधन, अंकलेश्वर और कड़कनाथ) के चूजों से 112 परिवारों को लाभान्वित किया गया। अजोला की 10 इकाई की स्थापना की गई । इससे किसान के मुर्गियों के दाना खर्च में

30-35 प्रतिशत की कमी पाई गई और दुधारू पशुओं में दुग्ध उत्पादन बढ़ने के साथ-साथ प्रजनन क्षमता में सुधार हुआ।

बीजू बकरा प्रदर्शन

केन्द्र द्वारा चयनित गाँवों में चार बीजू बकरों के प्रदर्शन दिए गए। वहीं, देशी नस्ल की गायों में सुधार हेतु दो गिर नस्ल के साण्ड किसानों को उपलब्ध कराये गए। जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु 20 वर्मी कम्पोस्ट इकाईयों से 20 किसानों को लाभान्वित किया गया। 20 किसानों को वेस्ट डीकम्पोजर बनाने का प्रशिक्षण और प्रदर्शन दिया गया। 40 किसानों को उन्नत किस्म का बीज भण्ड़ारण और बीज की उचित कीमत हेतु 40 स्टोरेज बिन के प्रदर्शन दिए गए। कवीके के इन कार्यक्रमों के माध्यम से जनजातीय चयनित परिवारों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। इन गतिविधियों से किसानों की आय में बढ़ोतरी के साथ-साथ पोषण स्तर में सुधार हुआ । साथ ही, किसानों में जागरूकता आई है।

आत्म अनुशासन से लक्ष्य प्राप्ति

कम्युनिटी पुलिसिंग टू बिल्ड अवेयरनेस कार्यक्रम

उदयपुर (कास)। कम्युनिटी पुलिसिंग टू बिल्ड अवेयरनेस एण्ड ट्रस्ट कायक्रम के तहत एनसीसी कैडेट्स और पुलिस अधिकारियों के मध्य खुली वार्ता का आयोजन हुआ। जिसमें पुलिस अधिकारियों ने बच्चों से सुरक्षा संबंधित मुद्दों और सामुदायिक पुलिसिंग पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दशरथ सिंह ने कहा कि वर्तमान में किशोर वर्ग में नशे की प्रवृत्ति और आधुनिक जीवन शैली के प्रति आकर्षण से कर्तव्य राह से भटकने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जिसके लिए यदि आत्म अनुशासन और कर्तव्य बोध पर ध्यान दिया जाए तो लक्ष्य प्राप्ति संभव हैं। उन्होंने स्वस्थ शरीर और आत्म अनुशासन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कैडेट्स अपने क्षेत्र में किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधियों की सूचना पुलिस को दें। कमांडिंग ऑफिसर सुधाकर त्यागी, सैकण्ड ऑफिसर जीतेन्द्र कुंवर और सीटीओ पल्लवी जोशी ने भी कार्यक्रम को सम्बोधित किया। अतिथियों के द्वारा कैडेट्स को सर्टिफिकेट्स और बैच वितरित किए गए।

बनेंगे पुलिस अधिकारी

प्रशिक्षु आरपीएस नियति शर्मा ने कैडेट्स से संवाद करते हुए जब बालिका वर्ग से पूछा कि कितनी कैडेट्स पुलिस में सेवाएं देना चाहती हैं तो सभी बालिकाओं ने जोश के साथ पुलिस में सेवा देने के लिए हामी भरी। नियति शर्मा ने पुलिस द्वारा रेंज स्तर पर प्रारम्भ किए गए काम्बेट कार्यक्रम के अर्न्तगत चुने गए कॉम्बेट वॉरियर्स से कहा कि कैडेट्स के साथ पुलिस विभाग का यह संवाद समाज और शैक्षिक संस्थानों में बाल संरक्षण और दूसरे कर्तव्यों में भूमिका को सुनिश्चित करेगा।

कैम्पस साक्षात्कार में छात्रों का चयन

उदयपुर (कास)। डेयरी और खाद्य विज्ञान प्रौद्योगिकी महाविद्यालय के द्वारा आयोजित कैम्पस साक्षात्कार में एक दर्जन से अधिक विद्यार्थियों का गुजरात के डेयरी संयंत्र में चयन हुआ है। महाविद्यालय के प्लेसमेन्ट प्रभारी इंजीनियर अशोक वर्डिया ने बताया कि केम्पस साक्षात्कार में सूरसागर डेयरी छः छात्रो का और सरहद डेयरी द्वारा भी छः छात्रों का नौकरी हेतु चयन किया गया। चयनित अभियार्थियों को सूर सागर और सरहद डेयरी विभिन्न प्रसंस्करण संयंत्रो में 1 वर्ष का प्रशिक्षण देगी । उसके पश्चात रु 6.50 लाख के वार्षिक वेतन पर नौकरी पर रखेगी। प्रशिक्षण के दौरान भत्ते के रूप मे प्रतिमाह रू 25000/-प्रदान किए जायेंगे। आपको बता दें कि सूर सागर डेयरी में प्रतिदिन 2.5 लाख लीटर दुध की प्रोसेसिंग होती है। वहीं, सरहद डेयरी में भी 2.5 लाख लीटर दुध की प्रोसेसिंग होती है। यह देश की एकमात्र डेयरी है, जहा ऊंट के दुध की प्रोसेसिंग करके मूल्यवर्धक दूध पदार्थो का उत्पादन किया जा रहा हैं।

बगीचा रेखांकन - स्थापना प्रशिक्षण सम्पन्न

उद्यानिकी में मशीनीकरण से बढ़ेगी आय

कोटा। कृषि विश्वविद्यालय कोटा के प्रसार शिक्षा निदेशक डॉ. केएम गौत्तम ने किसान आय में बढोत्तरी के लिए उद्यानिकी फसलोत्पादन में मशीनरी के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि मशीनरी के उपयोग से समय और श्रम की बचत संभव है। साथ ही, उत्पादन में भी इजाफा होता है। डॉ. गौत्तम कृषि विज्ञान केन्द्र, कोटा द्वारा बगीचा रेखांकन और स्थापना पर आयोजित किसान प्रशिक्षण के समापन सत्र को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आय और उत्पादन बढ़ाने के लिए किसान को जागरूक बनाने की जरूरत है। ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम से किसान के कौशल में निखार आता है। साथ ही, कार्य दक्षता को बढ़ावा मिलता है। निदेशक (पी.एम.ई.)डॉ. ममता तिवारी ने कहा कि फल-सब्जी का प्रसंस्करण करके इन्हें अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। साथ ही, उत्पाद की अच्छी कीमत भी मिलती है। केन्द्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक महेन्द्र सिंह ने प्रशिक्षण की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि फलोद्यान किसान की आर्थिकी को मजबूती प्रदान करता है। साथ ही, रोजगार भी सृजित करता है। प्रशिक्षण में डॉ. एमके गर्ग ने पशुपालन, सहायक निदेशक उद्यान नन्द बिहारी मालव ने उद्यान विभाग की योजनाओं, शस्य वैज्ञानिक डॉ. केएम शर्मा ने खरीफ फसल उत्पादन तकनीक और गृह वैज्ञानिक गुजंन सनाढ्य ने फल-सब्जी प्रसंस्करण तकनीक और किचन गार्डन के बारे में बताया। प्रशिक्षण में 32 किसानों ने भाग लिया।

प्लास्टिक मल्च पर दी जानकारी

नागौर। कृषि विज्ञान केन्द्र के द्वारा मिर्च फल में प्लास्टिक मल्च का महत्व पर निम्बा का बास निवासी किसान हनुमानाराम बुगालिया के खेत प्रक्षेत्र दिवस आयोजित किया गया। केन्द्र प्रभारी डॉ गोपीचंद सिंह ने किसानों को प्लास्टि मल्च उपयोग से होने वाले फायदों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि बागवानी फसलों में फल, फूल, सब्जियां और औषधीय फसलों से किसानों को काफी लाभ मिला है। केन्द्र की उद्यानिक वैज्ञानिक डॉ. अनोप कुमारी ने बताया कि जिनमें किसान लम्बे अर्से से ही बागवानी फसलें उगा रहे हैं जो कि अल्पकालीन से लेकर दीर्घकालीन प्रवृति की होती है । इन फसलों का उत्पादन पानी की कमी, खरपतवार, श्रमिकों की अनुपलब्धता, रोग-कीट, मौसम आदि कारकों से प्रभावित होता है। इन समस्याओं से बचने के लिए किसान लम्बे समय से सूखे पत्ते, धान का भूसा, पुआल, नारियल का छिलका, टहनियां और घास इत्यादि का उपयोग पलवार के रूप में करते आ रहे हैं । लेकिन इन सभी की ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होने के कारण स्थानीय स्तर पर उपलब्धता नहीं हो पाती है। लेकिन प्लास्टिक फिल्म बाजार में सहजता से उपलब्ध हो जाती है जो अन्य प्रकार की मल्चिंग की विधियों से ज्यादा उपयुक्त है।

यह दी जानकारी

प्रशिक्षण प्रभारी डॉ. रामराज मीणा ने बताया की प्रशिक्षण में किसानों को कोटा संभाग में फल बगीचों की संभावना, फल बगीचा रेखाकंन, मिट्टी-पानी जांच का महत्व, बगीचा हेतु स्थान चयन, पशुपालन-उद्यानिकी में आर्थिक संबंध, अमरूद, बेर, आवंला, नीबू, संतरा की उन्नत खेती, मातृ बगीचा स्थापना, फल-सब्जियों में बूंद-बूंद सिंचाई और फल-सब्जी प्रसंस्करण पर जानकारी दी गई।

सहकार मसाला मेले में 90 लाख का कारोबार

मेले का आज होगा समापन

जयपुर (कास)। तेज धूप और धूल भरी आंधियों का मौसम भी जयपुरवासियों को जवाहर कला केन्द्र में आयोजित हो रहे राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले में आने से नहीं रोक पा रहा है। गत 8 दिनों में 90 लाख रुपये से अधिक के मसालों की खरीद इस बात का प्रमाण है। सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार नीरज के पवन ने बताया कि मसाला मेले में प्रदेश के सभी क्षेत्रों के बेहतरीन गुणवत्तापूर्ण मसाले प्रतिस्पर्धी और उचित मूल्य पर उपलब्ध कराये जा रहे हैं। इस बार मेले में केरल, तमिलनाडु और पंजाब के मसाले उपलब्ध कराये जा रहे हैं। महिलाओं की पसन्द को देखते हुये राज्यपाल पदक से सम्मानित कैथून की सहकारी समिति द्वारा अकीला बानों के हाथों से तैयार की गई कोटा डोरिया, मूंगा की साड़ियां, कुर्ता और दुपट्टों की पूरी रेंज उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तीकरण को बढावा देने की दृष्टि से मेले में महिलाओं द्वारा तैयार किये गये हस्तनिर्मित उत्पादों की बिक्री भी की जा रही है। कॉनफैड द्वारा शरबती गेहूं, बूंदी का बासमती चावल, सूखे मेवे, विभिन्न प्रकार के शरबत, ठण्डाई, अर्क सहित उपयोगी उत्पाद उपलब्ध कराये गये हैं। गौरतलब है कि राष्ट्रीय सहकार मेले का समापन आज होगा।

बैठक | प्रदेशभर के सीईओं के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग

योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग जरूरी

जयपुर। ग्रामीण विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिवउ राजेश्वर सिंह ने वीडियो कान्फ्रेसिंग के जरिये मुख्यालय के अधिकारियों सहित प्रदेश के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ विभिन्न योजनाओं की प्रगति जानी। उन्होंने अधिक ारियों को मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना की तरह ग्रामीण विकास की दूसरी योजनाओं की प्रभावी मॉनीटरिंग के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि मनरेगा के तहत गत 2500 लाख मानव श्रम दिवस के बजट के विरूद्ध 29.42 लाख कार्य दिवस सृजित कर 117 प्रतिशत की वृद्धि अर्जित की है। इसके चलते राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर आ गया है। अपेक्षा से कहीं अधिक लक्ष्य हासिल करने के लिए सभी अधिकारियों द्वारा टीम भावना से किये कार्य की उन्होंने सराहना की। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत 5.88 लाख परिवारों को 100 दिन का रोजगार दिया गया। जो कि पिछले 8 वर्षों में सबसे अधिक है। पूरे देश में 100 दिन पूरे होने के मामले में राजस्थान तीसरा स्थान रखता है। आयुक्त मनरेगा एवं निदेशक स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण पीसी किशन ने अधिकारियों को मनरेगा कर्मियों को समय पर भुगतान, कार्य दिवस सृजन व औसत मजदूरी की दर पर ध्यान देकर आम जन को ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध करवाने पर जोर दिया। उन्होंने सभी सीईओ, एसीईओ से योजनाओं में लक्ष्य अर्जित करने के निर्देश दिये। कार्यक्रम के दौरान अतिरिक्त आयुक्त ईजीएस विश्राम मीणा, परियोजना निदेशक और उप सचिव हितबल्लभ शर्मा, परियोजना निदेशक ईजीएस राजेन्द्र सिंह केन, परियोजना निदेशक एसएपी विनिता सिंह, राज्य नोडल अधिकारी पीएमवाईजी जयपाल सिंह मेडतिया, अधीक्षण अभियन्ता के.के.शर्मा सहित दूसरी योजनाओं के अधिकारी उपस्थित थे।

पीएम आवास में 87.72 प्रतिशत लक्ष्य हासिल

उन्होंने कहा कि वर्ष 2017-18 में 2 लाख काम प्रदेश की ग्राम पंचायतों में हुए थे। उसकी तुलना में वर्ष 2018-19 में 4 लाख काम पूर्ण हुए है जो हाल के वर्षों में सबसे अधिक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 6.87 लाख धर के निर्माण के लक्ष्य के विरूद्ध 6.017 लाख धरों का निर्माण कर 87.72 प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दूसरी ग्रामीण विकास योजनाओं यथा स्थानीय सांसद, विधायक, डांग, मगरा, मेवात विकास की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि इनके तहत 1878.20 करोड़ के कुल आंवटन के विरूद्ध 3123 करोड़ खर्च कर 20915 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। यह लक्ष्य पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा रहा है।

23760 स्वयं सहायता समूह

प्रदेश में 17331 स्वंय सहायता समूहों के गठन के लक्ष्य के विरूद्ध 23760 स्वंय सहायता समूहों का गठन किया गया जो कि लक्ष्य का 156 प्रतिशत है। इन स्वंय सहायता समूहों को बैंकों के माध्यम से सहकारी साख ऋण उपलब्ध कराने में 98 प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने पर अधिकारियों को बधाई दी।

2.66 करोड़ किसानों को दूसरी किश्त जारी

पीएम-किसान योजना

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) की दूसरी किश्त 2.66 करोड़ किसानों के खाते ट्रांसफर की जा चुकी है, इसके अलावा किस्त का भुगतान 3.11 करोड़ लाभर्थियों को मिल चुका है। इसके तहत हर किसान के बैंक खाते में 2-2 हजार रुपये ट्रांसफर किए गए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह द्वारा जानकारी के अनुसार पीएम-किसान योजना के तहत उत्तर प्रदेश में 1,11,69,349 लाभार्थियों को पहली किस्त और राज्य के 1,08,48,667 किसानों को दूसरी किस्त जारी की जा चुकी है। लोक सभा चुनावों के चलते लाभ हस्तांतरण की प्रक्रिया चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार कुछ धीमी हुई है जो पुन: तेज और समयबद्ध कर दी जाएगी।

प्रामाणिक बैंक खातों में राशि

उन्होंने बताया कि योजना का कार्यान्वयन इसके प्रचलनात्मक दिशा-निर्देशों तथा पूरी तरह कंप्यूटरीकृत त्रुटिरहित तंत्र के अनुसार किया जा रहा है। इसके अंतर्गत तीन स्तर पर किसानों द्वारा दी गई सूचना/डाटा और उनके बैंक खातों की प्रामाणिकता की जांच करने के बाद ही केंद्र सरकार द्वारा लाभार्थियों को उनके बैंक खातों में योजना की राशि सीधे आनलाइन प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) पद्धति से भेजी जाती है।

लाभार्थी किसानों की सूची दे राज्य सरकार

उन्होंने बताया कि इस संबंध में लाभार्थी किसानों की सूची और सभी संबंधित डाटा राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। लाभ हस्तांतरण की पूरी प्रि या बैंकों के त्रुटिरहित, सशक्त और सुरक्षित तंत्र के द्वारा होती है। अतः योजना के कार्यान्वयन में किसी तरह की त्रुटि की गुंजाइश नहीं है। पुनः, सभी बैंकों को वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा स्पष्ट निर्देश जारी किए गये हैं कि योजना के अंतर्गत हस्तांतरित वित्तीय लाभ की राशि में से बैंक पिछले ऋण आदि के संबंध में अपना कोई भी बकाया वसूल नहीं करेंगे। उन्होंने राज्य सरकारों से पात्र किसानों की सूचना भिजवाने की बात भी कहीं है।

रिक्त पदों के चलते राजस्व का नुकसान

छबड़ा कृषि उपज मंडी के हालात

बारां। अ श्रेणी कृषि उपज मंडी में गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष साढ़े तीन करोड़ की आय कम हुई है। मंडी सचिव सहित कई कार्मिकों के पद रिक्त होने के चलते व्यापारियों की ओर से की जाने वाली जिंसों की खरीद-फरोख्त पर मंडी प्रशासन का कोई अंकुश नहीं है। कार्यवाहक मंडी सचिव मनोज मीणा ने बताया कि वर्ष 2017-18 में छबड़ा मंडी की कुल आय नौ करोड़ 66 लाख 53 हजार रुपए रही। वर्ष 2018-19 में मंडी की आय छह करोड़ 25 लाख 78 हजार रुपए रही। गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष मंडी की आय तीन करोड़ 40 लाख 75 हजार रुपए कम रही। कस्बे की मुख्य मंडी की आय गत वर्ष 378.28 से घटकर इस वर्ष 296.66 लाख रही। गौण मंडी छीपाबड़ौद की आय गत वर्ष 142.71 लाख के स्थान पर 118.76 लाख रही। छीपाबड़ौद लहसुन मंडी में गत वर्ष भाव ठीक थे। इस वर्ष भाव कम रहने के कारण यहां आय की गिरावट सर्वाधिक रही। गत वर्ष 417.59 लाख की तुलना में इस वर्ष 185.11 लाख की आय रही। इस तरह इस वर्ष 232.48 लाख की आय लहसुन मंडी में कम हुई। वहीं हरनावदा शाहजी में 27.95 की तुलना में 25.25 लाख की आय हुई।

कार्मिकों के पद रिक्त

कस्बे में स्थित कृषि उपजमंडी में मंडी सचिव का पद पिछले तीन वर्षों से रिक्त चला आ रहा है। बारां में कार्यरत सचिव मनोज मीणा को अतिरिक्त चार्ज दे रखा है। मंडी में सात एलडीसी और एक यूडीसी, लेखाकार सहित जमादारों के सभी पद रिक्त चले आ रहे हैं। एक एलडीसी को अटरू से यहां तीन दिन के लिए नियुक्त कर रखा है। मंडी प्रशासन में अधिकांश पद रिक्त होने के चलते यहां व्यापारियों पर कोई अंकुश नहीं रहा। ठेके पर लगे कार्मिक व्यापारियों से सांठगांठ कर मनमानी कर मंडी प्रशासन को आर्थिक हानि पहुंचा रहे हैं। मंडी के बाहर भी धडल्ले से अवैध रूप से जिंसो की खरीद-फरोख्त जारी है। वहीं कार्यवाहक मंडी सचिव मनोज मीणा ने बताया कि लहसुन के भावों में कमी के चलते आय में गिरावट आई है।

भड़कने लगी दलहन की कीमतें

सप्ताभर में अरहर-चने के भाव 200-500 रूपए तक बढ़े

जयपुर (कास)। किसानों का दलहन बिकने के बाद अब दाल की कीमते तेजी दर्शाने लगी है। सप्ताहभर में दलहन के दामों में 500 रुपये तक की बढोत्तरी देखी गई है। उत्पादक मंडियों में अरहर के भाव बढ़कर 6,000 से 6,100 रुपये प्रति क्विंटल हो गए है। जबकि , चना के भाव भी बढ़कर 4,600 रुपये प्रति क्विंटल हो गए हैं। दलहन कारोबारियों के अनुसार दैनिक आवक कम होने के कारण अरहर, चना और उड़द की कीमतों में तेजी आई है। मंडी में अरहर के भाव बढ़कर 6,000 से 6,100 रुपये प्रति क्विंटल हो गए। सप्ताहभर में अरहर की कीमतों में 400 से 500 रुपये और उड़द की कीमतों में 300 से 400 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी आ चुकी है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने अरहर का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 5,675 रुपये और उड़द का समर्थन मूल्य 5,600 रुपये प्रति क्विंटल तय किया हुआ है।

चना आयात पर 60 फीसदी शुल्क

दलहन कारोबारी राधाकिशन गुप्ता के अनुसार चना की दैनिक आवक कम होने से इसकी कीमतों में सप्ताहभर में करीब 200 से 250 रुपये की तेजी आई है। चना के भाव 4,500 से 4,600 रुपये प्रति क्विंटल हो गए हैं जबकि चना का एमएसपी केंद्र सरकार ने 4,620 रुपये प्रति क्विंटल तय किया हुआ है। उन्होंने बताया कि चालू रबी में चना का उत्पादन पिछले साल से कम होने का अनुमान है, जबकि चना के आयात पर केंद्र सरकार ने 60 फीसदी का आयात शुल्क लगाया हुआ है। इसीलिए चना की कीमतों में तेजी आई हैं।

दलहन आयात की मात्रा तय

उधर, केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 6.5 लाख टन दालों के आयात को मंजूरी दी हुई है। चालू वित्त वर्ष के लिए मूंग और उड़द के डेढ़-डेढ़ लाख टन आयात को, और अरहर के दो लाख टन और मटर का डेढ़ लाख टन आयात करने की मंजूरी दी हुई है। इसके अलावा करीब पौने दो लाख टन अरहर का मोजाम्बिक से सरकारी एजेंसियों के माध्यम से होगा। चना के आयात पर 60 फीसदी और मसूर के आयात पर 30 फीसदी आयात शुल्क लगाया था। वित्त वर्ष 2018-19 के पहले दस महीनों अप्रैल से जनवरी तक 21 लाख टन दालों का आयात हुआ था।

अरहर और चना का उत्पादन कम

कृषि मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2018-19 में अरहर का उत्पादन घटकर 36.8 लाख टन होने का अनुमान है जबकि , पिछले साल इसका उत्पादन 40.2 लाख टन का हुआ था। चना का उत्पादन भी चालू रबी में घटकर 103.2 लाख टन होने का अनुमान है । जबकि, पिछले साल 111 लाख टन चना का उत्पादन हुआ था। दलहन का कुल उत्पादन फसल सीजन 2018-19 में बढ़कर 240.2 लाख टन होने का अनुमान है । जबकि, पिछले साल 239.5 लाख टन का ही उत्पादन हुआ था।

कृषि जिंस भाव

जयपुर

मक्का	2400-2000
ग्वार	4100-3800
सरसों	3700-3600
चना	3700-3500

भीलवाड़ा

गेहूं	2050-1750
चना	4000-3900
सरसों	3400-3200
मक्का	2214-2100

जोधपुर

सरसों	4100-3300
जीरा	17000-12300
बाजरा	2200-1950
चना	4150-4000

चौमूं

गेहूं	1758-1700
सरसों	3465-3420
बाजरा	2016-1900
चना	4030-3980

दौसा

सरसों	3520-3200
गेहूं	1840-1620
बाजरा	2140-2000
चना	4090-3890

कोटपूतली

सरसों	3550-3400
जौ	1710-1650
गेहूं	1800-1700
चना	4000-3800

लालसोट

सरसों	3577-3200
गेहूं	1851-1650
सौंफ	8825-4600
चना	4085-4050

टोंक

सरसों	3596-3358
गेहूं	1800-1706
जौ	1729-1650
चना	4016-3930

अब तक 10.58 लाख टन गेहूं की हुई खरीद

तय लक्ष्य से पिछड़ी प्रदेश में गेहूं खरीद

जयपुर। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भारतीय खाद्य निगम के द्वारा किसानों से की जा रही गेहूं की खरीद तय लक्ष्य से पिछड़ती नजर आ रही है। प्रदेश में अब तक समर्थन मूल्य पर 10.58 लाख टन गेहूं की खरीद ही हुई है। जबकि, खरीद का लक्ष्य 17 लाख टन का तय किया हुआ है। पिछले रबी में राज्य से 15.32 लाख टन गेहूं की खरीद हुई थी। कृषि आयुक्तालय के अनुसार चालू रबी में गेहूं का उत्पादन 113.60 लाख टन होने का अनुमन है। गौरतलब है कि एमएसपी पर गेहूं की खरीद प्रदेश में ही नहीं, दूसरे राज्यों में भी लक्ष्य से काफी कम हुई है। उत्तराखंड से 39,000 टन, चंडीगढ़ से 12,000 टन और गुजरात 5,000 टन और हिमाचल प्रदेश से एक हजार टन गेहूं की खरीद समर्थन मूल्य पर हुई है। वहीं, हरियाणा और पंजाब से तय लक्ष्य से ज्यादा गेहूं की खरीद दर्ज हुई है। सबसे बड़े उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश के साथ ही मध्य प्रदेश से खरीद तय लक्ष्य से कम हुई है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के अनुसार चालू रबी सीजन में हरियाणा से रिकार्ड 93.08 लाख टन गेहूं की खरीद हो चुकी है । जबकि, खरीद का लक्ष्य 85 लाख टन का तय किया गया था। पिछले रबी सीजन में राज्य से 87.84 लाख टन गेहूं की खरीद एमएसपी पर हुई थी। पंजाब से चालू रबी विपणन सीजन 2018-19 में गेहूं की सरकारी खरीद बढ़कर 126.40 लाख टन की हो चुकी है । जबकि , खरीद का लक्ष्य 125 लाख टन का तय किया गया था। राज्य से पिछले रबी सीजन में समर्थन मूल्य पर 126.92 लाख टन गेहूं की खरीद हुई थी।

यूपी-एमपी में प्रदेश जैसा हाल

सबसे बड़े गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश से चालू रबी में समर्थन मूल्य पर केवल 25.30 लाख टन गेहूं ही खरीदा गया है। जबकि , गेहूं खरीद का लक्ष्य 50 लाख टन का तय किया गया है। पिछले साल राज्य से समर्थन मूल्य पर 52.94 लाख टन गेहूं खरीदा गया था। वहीं, मध्य प्रदेश से चालू रबी में एमएसपी पर 63.12 लाख टन गेहूं की खरीद हुई है । जबकि , खरीद का लक्ष्य 75 लाख टन का तय किया हुआ है। पिछले रबी में राज्य से 73.13 लाख टन गेहूं की खरीद हुई थी।

उत्पादन अनुमान ज्यादा

चालू रबी में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद का लक्ष्य 356.50 लाख टन का तय किया है जबकि पिछले रबी सीजन में 357.95 लाख टन गेहूं की खरीद एमएसपी पर की थी। केंद्र सरकार ने चालू रबी विपणन सीजन के लिए गेहूं का एमएसपी 1,840 रुपये प्रति क्विंटल तय किया हुआ है। जबकि, पिछले रबी में गेहूं की खरीद 1,735 रुपये प्रति क्विंटल की दर से हुई थी। मध्य प्रदेश में राज्य सरकार गेहूं की खरीद पर किसानों को 160 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस दे रही है। कृषि मंत्रालय के अनुसार चालू रबी में गेहूं का रिकार्ड 991.2 लाख टन उत्पादन का अनुमान है । जबकि, पिछले साल 971.1 लाख टन का उत्पादन हुआ था।

जैविक पशुपालन और देसी गौवंश पर होगा अनुसंधान

राजुवास में दशाब्दी वर्ष समारोह आयोजित

बीकानेर (कास)। राजस्थान पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय ने अपना 10वां स्थापना दिवस समारोहपूर्वक मनाया। इस मौके पर भैंस और गौवंश के केन्द्रीय अनुसंधान संस्थानों के साथ दो अलग-अलग करार (एम.ओ.यू.) किए गए। साथ ही, बांझपन निवारण और श्वानों में एंटी रेबीज टीकाकरण नि:शुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। समारोह में विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. विष्णु शर्मा ने कहा कि विश्वविद्यालय दशाब्दी वर्ष में नए संकल्प योजनाओं और कार्य संस्कृति के साथ आगे बढेगा। उन्होंने बताया कि विश्व में पशु विज्ञान के क्षेत्र में अंतरिक्ष आधारित तकनीक, अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी केन्द्रों की स्थापना करने वाला राजुवास पहला विश्वविद्यालय बना है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष में पशुचिकित्सा शिक्षा जागरूकता अभियान के साथ-साथ जैविक पशुपालक संवेदीकरण, देशी गोवंश प्रदर्शन और पशु रोग निदान सेवाओं के माध्यम से किसानों और पशुपालकों को लाभान्वित किया जाएगा। सभी संकायों में कौशल विकास और शैक्षिक संसाधनों का सुदृढीकरण करके गुणवत्तायुक्त शिक्षण और अनुसंधान कार्यों को प्राथमिकता से लागू किया जाएगा। विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. एके गहलोत ने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा गत 9 वर्षों में कायम की गई उत्कृष्टता की रफ्तार को आगे बढ़ाने की हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि देश में राजुवास की एक ब्रान्ड रूप में पहचान बनी है। महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. भागीरथसिंह बिजारणियां ने कहा कि विश्वविद्यालय को दशाब्दी वर्ष को चुनौति के रूप में संकल्प के साथ आगे ले जाने की जरूरत है। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. एच.डी. चारण ने कहा कि आने वाला दशक पशुपालन और कृषि का है। तकनीकी विश्वविद्यालय राजुवास के साथ मिलकर कार्य करने का इच्छुक है। इस अवसर डीन-डायरेक्टर फैकल्टी सदस्य, कर्मचारी और विद्यार्थी उपस्थित थे। तीनों संगठक महाविद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने इस अवसर पर रंगारग प्रस्तुतियां दी।

इनसे हुआ एमओयू : केन्द्रीय गौवंश अनुसंधान संस्थान, मेरठ के निदेषक डॉ. एनवी पाटिल ने बताया कि संस्थान में भ्रूण प्रत्यारोपण, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और देशी गोवंश की 43 विभिन्न प्रजातियों के अनुसंधान का लाभ एम.ओ.यू. होने से राजुवास को लाभ मिलेगा।

मुर्गीपालन से आमदनी

मुर्गी पालन व्यवसाय अण्डा एवं मांस दोनों के ही उत्पादन के लिए किया जाता है। लेकिन आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि अण्डा उत्पादन से ज्यादा मुनाफा ब्रॉयलर पालन यानि मांस उत्पादन में होता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मांस उत्पादन के लिए चूजें 40-45 दिन में तैयार हो जाते हैं। जबकि अण्डा उत्पादन के लिए तैयार होने में कुक्कुट को साढ़े पांच महीने तक लग जाते हैं। ऐसे मुर्गे जिन्हें सिर्फ मीट प्राप्त करने के लिए पाला जाता है, उन्हें ब्रायलर कहते हैं। इन मुर्गों का पालन ही ब्रॉयलर पालन कहा जाता है। ये खास किस्म के मुर्गे होते हैं। जिनकी शरीरिक बढ़त बहुत तेजी से होती है। ब्रायलर पालन व्यवसाय को छोटे स्तर से शुरू करके, अंशकालिक व्यवसाय के तौर पर भी अपनाया जा सकता है।

चूजें का चुनाव

ब्रायलर पालन में चूजें का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण होता है। चुस्त, फुर्तीले, चमकदार आंख वाले तथा समान आकार के चूजे उत्तम होते हैं। स्वस्थ चूजें की पिण्डली या पैर की खाल चमकदार होती है। चूजें को खरीदते समय ये ध्यान रखें कि पक्षी के वजन में अन्तर न हो। क्योंकि वजन में जितना अन्तर होगा, आमदनी उतनी घटती चली जाती है। चूजे किसी भी मान्यता प्राप्त व्यक्ति गत अथवा सरकारी संस्था से खरीदे जा सकते हैं।

ब्रायलर प्रजाति

ब्रायलर के लिए उपयुक्त प्रजातियां हैं कारीब्रो-विशाल, कारीरेनब्रो, कारीब्रो- मृत्युंजय और बड़े पालक के लिए वैनकॉक, हबबर्ड, पोनिक्स आदि प्रजाति है।

आवास की व्यवस्था

ब्रॉयलर पालन के लिए मुख्य तौर पर दो प्रकार के घर तैयार किये जाते हैं।

- **पिंजरा सिस्टम-** इसमें पक्षियों की ब्रूडिंग स्थिति (ब्रुंड में रखने की अवस्था) में 0.25 वर्ग फीट प्रति चूजा स्थान होना चाहिए और बढ़वार की स्थिति में आधा वर्ग फीट प्रति ब्रायलर चूजे के लिए स्थान होना चाहिए।
- डीप लिटर सिस्टम- इसमें फर्श पर पालन किया जाता है। इसमें ब्रूडिंग स्थिति में प्रति ब्रायलर चूज़े का स्थान 0.50 वर्ग फीट होना चाहिए और बढ़वार की स्थिति में 1.00 वर्ग फीट होना चाहिए।

तापमान का प्रबंधन

चूजे को ब्रूडर में रखने के बाद ये देखना चाहिए कि तापमान उनके लिए उपयुक्त है या नहीं। क्योंकि तापमान की कमी और अधिकता से चूजे की बढ़वार पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तापमान परिवर्तित होने पर चूजे असहजता के कारण अजीब तरह की गतिविधि करने लगते हैं। गर्मी ज्यादा होने पर बाड़े में कूलर की व्यवस्था ज़रूर कर दें। जब नए चूजे को बाड़े में रखा जाता है तो शुरुआति दो-तीन दिन तक बाड़े में 33 डिग्री सेन्टीग्रेड तापमान बनाए रखें और इस अवस्था के बाद बाड़े का तापमान 21 डिग्री सेन्टीग्रेड बनाए रखना होता है।

आर्द्रता से घातक

नमी बढ़ने पर चूजें का बिछावन गीला हो जाता है। जिससे सांस सम्बंधी कई समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसलिए आर्द्रता 50 से 60 प्रतिशत से ज्यादा होने पर उनका बिछावन समय-समय पर बदलना चाहिए।

नए चूजें की देखभाल

मुर्गीपालन में नये चूजे लाने व उनकी देखभाल के लिए मुर्गीघर को कीटणुनाशक दवाई डालकर पानी से धोना चाहिए तथा आंगन पर साफ -सुथरा होना चाहिए। मुर्गीघर का तापमान हीटर से नीयत करना चाहिए चूजें के लिए साफ व ताजा पानी हर समय उपलब्ध रखना होगा।

हवा का आवागमन

चूजे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए हवा का उचित आवागमन बहुत आवश्यक होता है। प्रति घंटे 3 से 5 बार कमरे की हवा को परिवर्तित करना चाहिए। पक्षी के मूत्र से बिछावन भीग जाता है। जिससे अमोनिया गैस इकट्ठा हो जाती है। इससे पक्षी की आंख में खुजलाहट होती है और शारीरिक वृद्धि भी रुक सकती है। इसलिए हवा के आवागमन का खास ध्यान रखना चाहिए।

रोशनी की व्यवस्था

ब्रायलर आवास में प्रकाश का प्रबंध आमतौर पर बल्ब से किया जाता है। 23 घंटे लगातार बाड़े में प्रकाश बनाए रखें और सिर्फ एक घंटा अंधेरा रखें, चाहे वह आवास खुले हों या बंद। शुरुआत के एक से 15 दिन तक 200 वर्ग फीट आकार के कमरे में 40-60 वॉट के बल्ब का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद 15 वॉट का बल्ब प्रकाश के लिए काफी होता है।

मुर्गी की छंटनी

मुर्गीपालन के लिए और महत्वपूर्ण अंग है मुर्गी की छंटनी नियमित रूप से करना ,खराब मुर्गी की छंटनी। मुर्गी के उत्पादन रिकार्ड को देखकर तथा उसके बाहरी लक्षण को ध्यान में रखकर खराब मुर्गी को हटाया जा सकता है।

पोषक आहार

ब्रायलर को शुरू से ही भर पेट खिलाएं । जिससे वे तेजी से बढ़ेंगे। ब्रायलर चूजे अंडे देने वाली मुर्गी की तुलना में काफी तेजी से बढ़ते हैं। वृद्धि की गति को ध्यान में रखकर इनके लिए दो प्रकार के आहार उपयोग में लाये जाते हैं-

स्टार्टर आहार- चूजों को शुरुआति दिन में दिए जाने वाले आहार को स्टार्टर कहते हैं। बाड़े में रखने के चार सप्ताह में ब्रायलर को स्टार्टर आहार दिया जाता है। जिसमें करीब व23 फीसदी प्रोटीन और करीब 3000 कैलोरी उर्जा होती है। इससे पक्षी का वजन और मांसपेशी का विकास तेजी से होता है।

फिनिशर आहार- पक्षी को चार सप्ताह के बाद से फिनिशर आहार देना होता है। इसमें ऊर्जा की मात्रा में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन, प्रोटीन की मात्रा घटा दी जाती है।

टीकाकरण

ब्रायलर का टीकाकारण कराना सबसे आवश्यक है। क्योंकि इससे मुर्गे गंभीर बीमारियों से बचे रहते हैं।

मैरेक्स टीका : चूजे को सबसे पहले मैरेक्स का टीका लगवाना चाहिए। जिससे उन्हें मैरेक्स बीमारी से सुरक्षा मिल सके। यह संक्रामक रोग चूजें को ही लगता है। इसलिए चूजें को हैचरी से बाड़े में रखने पर यह टीका लगवाना बहुत जरुरी है। इस रोग का प्रकोप होने पर उनकी टांगे और गर्दन कमजोर हो जाती है।

पिंजरा वाले पोल्ट्रीफार्म का नहीं होगा पंजीयन

जयपुर (कास)। केज सिस्टम यानी पिंजरा वाले पोल्ट्रीफार्म का अब पंजीयन नहीं होगा। हाईकोर्ट का हवाला देकर पशुपालन विभाग द्वारा इनका पंजीयन नहीं किया जा रहा है। एनीमल वैलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने केज सिस्टम वाले पोल्ट्रीफार्म में पशु क्रूरता होना माना था। इसके बाद हाईकोर्ट ने इस तरह के पोल्ट्रीफार्म के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया। पशुपालन विभाग के निदेशक ने जिलों को दिए निर्देश में कहा है कि केज प्रणाली वाले पोल्ट्रीफार्म का पंजीयन नहीं करें।

खुले में करें पालन : आपको बता दें कि प्रदेश में मुर्गीपालन लेअर और बॉयलर दो तरह से हो रहा है। इनमें लेअर में करीब 95 प्रतिशत केज सिस्टम वाले हैं। मालूम हो कि लेअर फार्म में 4 माह में प्रॉडक्शन शुरू हो जाता है, फिर मुर्गियां 18 माह तक अंडे देती हैं। लंबे समय तक मुर्गियां रखनी होती है। जीव दया संस्था ने तर्क दिया कि पिंजरे में बंद मुर्गियों को हवा-पानी सही तरीके से नहीं मिल पाता, न तो ठीक से हवादार स्थान मिलता है और न ही एरिएशन। खुले में घूम नहीं सकती। इसे पशु क्रूरता माना जाए।

कैलिफार्निया में केज सिस्टम हो चुका है बंद : केज सिस्टम वाले पोल्ट्रीफार्म के रजिस्ट्रेशन पर रोक का मामला हाईकोर्ट में पैंडिंग है, पोल्ट्री एसेसिएशन ने भी इसमें अपना पक्ष रखा है। अगली डेट जुलाई माह में दी गई है। अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में केज सिस्टम वाले पोल्ट्रीफार्म लगभग बंद हो चुके हैं।

घर बैठे हलधर टाइम्स मंगाने के लिए भर कर भेजें।

सदस्यता फार्म

दिनांक .....

हलधर टाइम्स साप्ताहिक ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पशुपालन, सहकारिता, ग्रामीण विकास, मशीनरी व संचार से जुड़ी आधुनिकतम एवं तकनीकी जानकारी किसानों व ग्रामीणों तक पहुंचाकर ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित कर रहा है। हलधर टाइम्स समय-समय पर भिन्न-भिन्न विषयों पर विशेषांकों का प्रकाशन भी करता है तथा अपने ग्राहकों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के भेजता है। अत: मुझे / हमें भी अंग्राकित पते पर हलधर टाइम्स डाक / कोरियर द्वारा भेजें।

सदस्यता राशि

☐ एक वर्ष रु. 250/- ☐ दो वर्ष रु. 450/- ☐ तीन वर्ष रु. 600/- ☐ पांच वर्ष रु. 1000/-

डाक से नियमित रुप से निम्न पते पर हलधर टाइम्स भेजने के लिए डिमान्ड ड्राफ्ट/मनीऑर्डर हलधर टाइम्स के नाम भेज रहा हूं।

नाम / संस्था का नाम .....

ग्राम ..... पोस्ट.....

तहसील ..... जिला.....

फोन ..... पिन कोड

राशि (रुपए) ..... बैंक का नाम .....

डिमान्ड ड्राफ्ट / मनीऑर्डर क्रमांक (डीडी/एमओ हलधर टाइम्स के नाम भेजें)

•सदस्यता रजिस्ट्रेशन क्रं. .....रसीद क्रं. .....

•मुझें हलधर टाइम्स के ग्राहक बनने की प्रेरणा (नाम, पता व अंशकालिक संवाददाता/प्रतिनिधि की सील) .....

..... ने दी है।

दिनांक ..... हस्ताक्षर

सदस्यता हेतु लिखे प्रसार प्रभारी →

हलधर टाइम्स

सी-17, पुरोहित जी का बास, सरकारी मिडिल स्कूल के पास, 22 गोदाम, जयपुर-302006

Ph.: 0141-4021593 ■ Telefax : 0141-2213100 ■ Visit us : www.haldhartimes.in

सब्जियों से देव, आय 6 लाख

देशकिशन धाकड़
मो. : 8003774790

किसान देवकिशन धाकड़ का कहना है कि परम्परागत खेती से परिवार का खर्च चलाना भी मुश्किल था। लेकिन, जबसे सब्जी उत्पादन से जुड़ा हूँ। हर साल आय का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। इससे मैं आधुनिक कृषि तकनीक को अपनाने के बारे में सोचने लगा हूँ। आपको बता दें कि देवकिशन 6 बीघा क्षेत्र में सब्जी फलसों का उत्पादन करता है। इन फसलों से सालाना 6-7 लाख रूपए की आय देश किशन को हो जाती है। वहीं, परम्परात फलसों से 2 लाख की आय इस किसान को होती है।

रिपोर्ट : शरद शर्मा

गोविंदपुरा, बारां। जमीन 35 बीघा। फिर भी आर्थिक तंगी का शिकार था किसान देवकिशन धाकड़। क्योंकि, फसलोत्पादन परम्परागत तौर-तरीकों से करता था। किसान की यह स्थिति थी 6 साल पहले। लेकिन, अब परिवार के आर्थिक हालात पूरी तरह से बदल चुके है। यह बदलाव आया है सब्जी उत्पादन से जुड़ने के बाद। 6 बीघा क्षेत्र से सालाना 6 लाख की आय लेने वाले देवकिशन का कहना है कि पहले फसली खर्च निकालने के बाद परिवार का खर्च चलाना भी भारी पड़ता था। लेकिन, सब्जी उत्पादन ने हालातों को बदल दिया है। किसान देवकिशन ने हलधर टाइम्स को बताया कि 10वीं में असफलता हाथ लगने के बाद खेती से जुड़ गया। दोबार परीक्षा देने का मन था। लेकिन, इसी बीच पिताजी का स्वर्गवास हो गया। परिवार के पालन की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। परिवार के पालन-पोषण के लिए छोटी उम्र में ही खेती-बाड़ी से जुड़ गया। पहले पुराने तौर-तरीको से परम्परागत फसलों का उत्पादन करता रहा। लेकिन, अथक मेहनत के बाद भी मुनाफा कम मिलता था। आय बढ़ाने के लिए क्षेत्र के दूसरे किसानों से प्रेरणा लेते हुए सब्जी उत्पादन करना शुरू किया। मैने सब्जी उत्पादन की शुरूआत आधा बीघा क्षेत्र से की। सब्जी फसलों से अच्छा मुनाफा मिला तो हौंसला बढ़ता रहा। वर्तमान में 6 बीघा क्षेत्र में सब्जी फसल का उत्पादन कर रहा हूँ।

उन्होंने बताया कि पहले तो सब्जियों की बुवाई साधारण तरीके से ही करता था। लेकिन, अब प्लास्टिक मल्च और सिंचाई के लिए ड्रिप का उपयोग कर रहा हूँ। उद्यान विभाग के सहायक निदेशक एनबी मालव ने बताया कि भले ही किसान देवकिशन की किताबी तालिम कम है। लेकिन, सब्जी उत्पादन से आय लेने के गुर अच्छे से सीख चुका है। सब्जी फसलों की बिक्री ग्रेड़िग के आधार पर करता है। इससे बाजार भाव अच्छे मिल जाते है। आपको बता दें कि किसान देवकिशन परम्परागत फसल में गेहूं, सोयाबीन, उड़द और सरसों का उत्पादन लेता है। इन फसलों से 2 लाख रूपए की आय मिल जाती है।

ऐसे बढ़ी आमदनी

6 साल पहले आधा बीघा क्षेत्र से 20-25 हजार रूपए की आय मिली। इसको देखते हुए मैंने हर साल थोड़ा-थोड़ा क्षेत्रफल बढ़ाना शुरू किया। परिणाम यह रहा कि 6 बीघा क्षेत्र सब्जी उत्पादन के अन्तर्गत आ चुका है। सब्जी फसल में भिंड़ी, बैंगन, ग्वार, चौला, तुरई, लौकी और ककड़ी का उत्पादन लेता हूँ। किसान देवकिशन ने बताया कि गर्मी की सब्जियों से अच्छी आय मिलती है। सर्दी के मौसम में सब्जियों के दाम गिर जाते है। ऐसे में सर्दी की फसल में केवल भिड़ी का ही उत्पादन लेता हूँ। इनके अलवा 10 बीघा क्षेत्र में लहसुन की बुवाई करता हूँ।

उन्नत पशुपालन

पशुधन में मेरे पास 1 गाय और 2 भैंस है। पशुधन आवास गृह वैज्ञानिक तरीके से तैयार किया हुआ है। प्रतिदिन 8-10 किलो दुग्ध का उत्पादन मिल रहा है। दुग्ध का विपणन नहीं करता हूँ। पशु अपशिष्ट से कम्पोस्ट खाद तैयार करके उपयोग लेता हूँ।

रोडु की शान अविशान

भेड़पालन से सालाना आय ढ़ाई लाख

रोडू गुर्जर
मो. : 8209370964

भेड़ नस्ल अविशान अब भेड़पालकों की आय ही नहीं, समाज में उनकी शोभा भी बढ़ा रही है। क्योंकि, गांवों में आज भी व्यक्ति की हैसीयत रेवड़ और खेती-बाड़ी से आंकी जाती है। अविशान का पालन करने वाले ऐसे ही भेड़पालक है रोडु गुर्जर। रोडु गुर्जर सालाना ढ़ाई लाख रूपए की आय भेड़ पालन से ले रहे है। इसके अलावा पशुपालन और खेती-बाड़ी भी कर रहे है। गौरतलब है कि अविशान नस्ल का विकास सीएसडब्ल्यूआरआई, अविकानगर के पशुधन वैज्ञानिकों ने किया है। यह नस्ल एक ब्यात में दो-तीन मेमनों को जन्म देती है। आपको बता दें कि किसान रोडु ने 10वीं पास करने के उपरांत रेवड़ पालन का काम शुरू किया है।

तांतिया, टोंक। हाइटेक कृषि के दौर में भेड़ पालन भले ही छोटा और श्रम साध्य व्यवसाय है। लेकिन, यह व्यवसाय भी किसान आय बढ़ाने की क्षमता रखता है। भेड़पालन से परिवार की आर्थिक स्थिति को सरसब्ज वाला एक किसान है रोडु गुर्जर। रोडु गुर्जर भेड़ और बकरी पालन से सालाना दो से ढ़ाई लाख रूपए की आय ले रहा है। इसके अलावा पशुपालन और फसल उत्पादन से भी अच्छी आय इस किसान को हो रही है। आपको बता दें कि वैज्ञानिक तरीके से भेड़पालन के लिए प्रदेश के तत्कालीन कृषि मंत्री डॉ. प्रभुलाल सैनी किसान रोडु गुर्जर को सम्मानित कर चुके है। किसान रोडु गुर्जर ने हलधर टाइम्स को बताया कि 10वीं पास करने के बाद भेड़ चराना शुरू कर दिया। उस समय संयुक्त परिवार था। पढ़ाई का ज्यादा महत्व नहीं था। जैसे ही 10वीं पास की। दादाजी ने मुझे भेड़ चराने की जिम्मेदारी सौंप दी। उस समय परिवार के पास भेड़ो की संख्या काफी अधिक थी। इस तरह मेरा जुड़ाव भेड़ पालन से हुआ। इसके बाद परिवार का बंटवारा होता गया और भेड़ो की संख्या कम होती गई। वर्तमान में मेरे पास 60-70 भेड़ और आधा दर्जन से अधिक बकरियां है। इनसे सालाना 2 लाख रूपए की आय मिल जाती है। उन्होंने बताया कि भेड़ पालन को और ज्यादा लाभकारी बनाने में केन्द्रीय भेड़ और ऊन विकास संस्थान, अविकानगर के पशुधन वैज्ञानिकों का सहयोग मुझे मिलता रहा है। भेड़ पालन से जुड़े अनुभव साझा करते हुए रोडु बताते है कि दो दशक पहले भेड़ रोगों के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। मुँह-खुर-पका, काला छेरा, फड़किया, माता रोग के प्रकोप को मेरे साथ गांव के दूसरे भेड़पालक प्राकृतिक प्रकोप मानकर रेवड़ को नुकसान उठाते रहे। इसके बाद अविकानगर के वैज्ञानिको ने गांव में पशु चिकित्सा शिविर और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना शुरू किया तो भेड़-बकरी में होने वाले रोग नियंत्रण के बारे में जानकारी मिली। फिर, मैने भेड़ो सहित दूसरे पशुओं को समय-समय पर टीका लगवाना शुरू किया। परिणाम यह रहा कि अब रोग से रेवड़ का नुकसान नहीं उठाना पड़ता है।

ऐसे बढ़ी आय

उन्होंने बताया कि 70 भेड़ो से 5-6 हजार रूपए सालाना की ऊन मिल जाती है। इसके अलावा 25-30 हजार रूपए मींगणी खाद की बिक्री से मिल जाते है। वहीं, 40-45 रूपए प्रतिकिलो की दर से दुग्ध बिक जाता है। इसके अलावा नर मेढ़ो की बिक्री से आय मिलती है। आपको बता दें कि किसान रोडु एक ब्यात में दो-तीन बच्चे देने वाली अविशान नस्ल की भेड़ो का पालन कर रहे है। उन्होंने बताया कि 5 बकरियाँ, 1 गाय और 2 भैंस मेरे पास है। प्रतिमाह 20 हजार की आय दुग्ध विपणन से हो जाती है। वहीं, सालाना 50 हजार रूपए की आय बकरा विपणन से मिल जाती है।

परम्परागत फसलों का उत्पादन

उन्होंने बताया कि मेरे पास 10 बीघा कृषि भूमि है। हम दो भाई पहले संयुक्त रूप से भेड़पालन से जुड़े हुए थे। इससे मिली आय से ही हमने 10 बीघा कृषि भूमि भी खरीदी है। परम्परागत फसलों में मूंग, ज्वार, मक्का, बाजरा की फसल लेता हूँ। सिंचाई के लिए कुआं है। लेकिन, भू-जल स्तर कम होने के चलते फार्मपौंड भी मैने बनाया है। इससे सिंचाई सुविधा का विस्तार हुआ है। परम्परागत फसलों से सालाना 1 लाख रूपए की आय मिल जाती है।

मृत्युदर में आई कमी

उन्होंने बताया कि वैज्ञानिकों से ज्ञात हुआ है कि एक भेड़ के लिए उसके ब्यात के एक महीना पहले से प्रतिदिन दाना खिलाने से भेड़ के दूध और मेमने की बढ़वार में बढ़ोतरी होती है। संस्थान किसान सहभागिता कार्यक्रम से जुड़ने के बाद भेड़ों में मृत्यु, रोगग्रस्त दर में कमी आई है। वहीं, स्वस्थ रेवड़, मेमनों के वजन में अंतर देखने को मिला है। अब उचित पोषण से 3 महीने के मेमने का वजन 17-18 किलोग्राम हो जाता है। संस्थान के शरीर क्रिया रसायन विज्ञान विभाग के माध्यम से मैं दो साल में तीन बार बच्चे लेने में सफल रहा हूँ।

स्टोरी इनपुट- डॉ.एलआर गुर्जर, राजकुमार चहल, एससी शर्मा, अरूण कुमार तोमर, सीएसडब्ल्यूआरआई, अविकानगर

बकरा पालन से सालाना 6 लाख

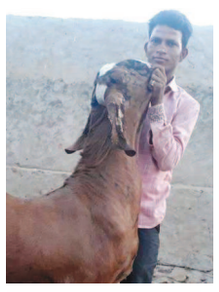

लालाभाई
मो. : 8239356295

गरीब की गाय कही जाने वाली बकरी अब किसानों को लखपति बनाने लगी है। पशुपालक लालाभाई से मिले, जो अपने परिवार का सारा खर्च बकरा विपणन से निकाल रहे है। उनका कहना है कि पहले दूसरों के लिए बकरी पालन का कार्य करता था। लेकिन, अब मैने बकरा-बकरी पालन को स्वयं का व्यवसाय बना लिया है। इससे सालाना 5-6 लाख रूपये की आय हो रही है। आपको बता दें कि ढ़ाका और नेपाल के किसानों के साथ लालाभाई कारोबार कर रहे है।

के ड़ल, अजमेर। के ड़ल गांव का लालाभाई। 12 वीं पास करने के साथ ही पढ़ाई छोड़ दी। युवा होने पर रोजगार की समस्या आई। कुछ नहीं सूझा तो पिताजी के साथ पुश्तैनी काम को विस्तार देने में जुट गए। अब सालाना 6-7 लाख रूपए की आय ले रहे है। आप सोच रहे होंगे कैसे ? तो बता दें कि लालाभाई किसानों से बकरों और बकरी की खरीद करते है। अपने फार्म हाउस पर उनका पालन-पोषण करते है। फिर, यू-ट्यूब, वाट्सअप का उपयोग करके ग्राहक तलाशते है। यही कारण है कि ढ़ाका और नेपाल के किसानों को उन्नत नस्ल के बकरे-बकरियों का विपणन कर रहे है। आपको बता दें कि लालाभाई के पास कृषि भूमि के नाम पर फार्म हाउस की जमीन है। इस पर बकरी वंश का पालन किया जाता है। लालाभाई ने हलधर टाइम्स को बताया कि पढ़ाई छोड़ने के बाद रोजगार की तलाश में था। सोचा कम पूंजी में कौनसा व्यवसाय करूं। इसी उधेड़बुन के बीच मैंने पैतृक व्यवसाय को ही विस्तार देने का मन बनाया। क्षेत्र के किसानों से सम्पर्क साधना शुरू किया। नस्ल के हिसाब से बकरों और बकरी की खरीद करता हूँ। फार्म हाउस पर बेहत्तर तरीके से पोषण करने के बाद बिक्री करता हूँ। यू-ट्यूब, वाट्सअप पर विड़ियो बनाकर अपलोड़ करता हूँ। ढ़ाका और नेपाल के बड़े किसानों से मेरा सम्पर्क ऐसे ही हुआ है। अब 600-700 की संख्या में प्रत्येक माह मांग के अनुरूप पशुओं का निर्यात कर रहा हूँ। मुझसे खरीद करने के बाद वहां के किसान पशुओं को एक माह अपने फार्म हाउस पर रखते है। ताकि, जलवायु का असर ज्ञात हो जाए। इसके बाद किसानों को बिक्री कर देते हे।

उन्नत पोषण

हरे चारे के अलावा बकरों को चना, जौ, दलिया आदि से बना फीड खिला रहा हूँ। प्रत्येक बकरे को प्रतिदिन 200 ग्राम दाना देता हूं।, जिससे उनका वजन तेजी से बढ़ रहा है। समय-समय पर बकरों के स्वास्थ्य की जांच करवा रहा हूँ।

घर बैठे आते है खरीददार

उन्होंने बताया कि एक दशक से ज्यादा समय से इस व्यवसाय को कर रहा हूँ। इसके चलते बडे महानगरों के व्यापारियों से अच्छे सम्पर्क बन चुके है। पशु व्यापारी घर बैठे बकरों की खरीद कर ले जाते है। आपको बता दें कि इस पशुपालक के द्वारा तैयार किए बकरे दिल्ली, कोलकता, मुबंई, पंजाब सहित दूसरे महानगरो में ऊंचे दामों पर बिक्री हो रहे है।

ऐसे होती है आय

उन्होंने बताया कि बकरों और बकरी के दाम नस्ल और वजन के हिसाब से तय होते है। फार्म हाउस पर सिरोही नस्ल की संख्या ज्यादा है। क्योंकि, इनके दाम अच्छे मिलते है। इसके अलावा तोतापुरी, सोजत, बरबरी, नागफनी, अजमेरी, जमुनापारी, कोटा, गुजरी, जाखरन आदि नस्ल की बकरी और बकरों का पालन करता हूँ। वर्तमान में 60 बकरे बिक्री को तैयार है। उन्होंने बताया कि बकरी के भाव 300-350 और बकरे के 400 रूपए प्रतिकिलो की दर से मिलते है।

20 साल गुणवत्ता के

श्री कृष्णा पेस्टिसाइड्स
गुणवत्ता ही पहचान है

गुणवत्तायुक्त उत्पाद
- क्रिशमिडा — इमिडा क्लोरोप्रिड 17.8 % एसएल
- क्रिशपैंडा — पैंडामैथलीन 30 % ईसी
- क्रिशान — कार्बण्डाजिम 12 % + मैंकोजेब 63 % डब्ल्यू.पी.
- क्रिशकिंग — ट्राइकोन्टानॉल जीआर 0.05 %
- क्रिशसल्फ — सल्फर 80 % डब्ल्यूडीजी
- क्रिशमेट — फोरेट 10 % सी.जी.
- मोनोक्रिश — मोनोक्रोटोफॉस 36 % एस.एल.
- क्रिशबान — क्लोरोपाइरीफॉस 20 %ई.सी.
- क्रिशवेल — फेनवलरेट 0.4 % डी.पी. व 20 % ई.सी.
- क्रिशथिऑन — मेलाथियॉन 5 % डी.पी. व 50 % ई.सी.

अन्य उत्पाद
- डायमिथोएट 30 % ई.सी.
- प्रोपोक्सर 1 % स्प्रे
- फास्फोमिडान 40 % एस.एल.
- साइपरमेथ्रिन 25 % ई.सी.
- डायक्लोरोवास 76 % ई.सी.
- सल्फर 85 % डी.पी.
- क्यूनालफॉस 1.5 % डी.पी.
- फाजालोन 35 % ई.सी.
- मैंकोजेब 75 % डब्ल्यू.पी.
- क्लोरोपाइरीफॉस 50 % + साइपरमेथ्रिन 5 % ई.सी.
- साइपरमेथ्रिन 3 % + क्यूनालफॉस 20 % ई.सी.

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें ए-335, ई-1, रोड नं. 17, विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर (राज.)-13 फोन: 0141-2460552, 98290-10740 E-mail : skp011@ymail.com

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक शरद शर्मा के द्वारा अम्बर ऑफसेट प्रा. लि., डी.एल. टॉवर, 3-ए, विद्याश्रम संस्थानिक क्षेत्र, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर से मुद्रित एवं सी-17, पुरोहित जी का बास, सरकारी मिडिल स्कूल के पास, 22 गोदाम, जयपुर-302006 से प्रकाशित।
संपादक : शरद शर्मा। फोन : 0141-4021593, फैक्स : 0141-2213100, ईमेल : haldhartimes@gmail.com or rediffmail.com (सभी मामलों का न्याय क्षेत्र जयपुर)